नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 026
दि. 29.10.2025,
बुधवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

केरल से उठी हिजाब की बहस ने फिर छेड़ी देशभर में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर चर्चा

(जीएनएस)। तिरुवनंतपुरम। भारत की कक्षाओं में फिर वही पुराना सवाल लौट आया है—क्या शिक्षा की एकरूपता और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी छात्रा के धार्मिक प्रतीक को सीमित किया जा सकता है? केरल में एक स्कूल और सरकार के बीच हिजाब पहनने को लेकर उठा विवाद अब केवल एक राज्य का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश की संवैधानिक आत्मा पर सवाल बनकर खड़ा है।

कोच्चि के पल्लुरुथी इलाके में स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल ने केरल सरकार के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें एक मुस्लिम छात्रा को हिजाब पहनकर कक्षा में आने की अनुमति दी गई थी। स्कूल ने कहा कि यह निर्देश सामान्य शिक्षा विभाग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है और सीबीएसई से संबद्ध संस्थान में राज्य सरकार दखल नहीं दे सकती। यह मामला जब अदालत पहुँचा, तो केरल सरकार ने जो हलफनामा पेश किया, उसने बहस की दिशा ही बदल दी। सरकार ने कहा कि हिजाब पहनना केवल धार्मिक पहचान का प्रतीक नहीं, बल्कि निजता, गरिमा और शिक्षा के मौलिक अधिकार से जुड़ा मुद्दा है।

सरकार ने अदालत में कहा कि किसी छात्रा को हिजाब पहनने से रोकना धर्मनिरपेक्ष शिक्षा से वंचित करने के बराबर है। हलफनामे में स्पष्ट कहा गया कि संविधान में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कोई भी संस्थागत एकरूपता हावी नहीं हो सकती। सरकार ने यह भी तर्क दिया कि राज्य के शिक्षा विभाग को सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों पर प्रशासनिक, वित्तीय और कार्यात्मक अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए यह मामला उनके दायरे में आता है।

सुनवाई के दौरान छात्रा के माता-पिता ने अदालत को बताया कि उन्होंने बेटी का नाम उस स्कूल से काटकर दूसरी जगह दाखिला करा दिया है। अदालत ने इस पर टिप्पणी की कि "समझदारी की जीत हुई है" और विवाद को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन इस

निर्णय के बावजूद बहस खत्म नहीं हुई—बल्कि यह अब और गहरी हो गई है।

केरल के शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने स्कूल प्रशासन के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि "किसी भी बच्चे को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।" उन्होंने स्कूल को निर्देश दिया कि वह यूनिफॉर्म से मेल खाता हुआ एक उपयुक्त हेडस्कार्फ़ डिज़ाइन करे ताकि अनुशासन और धार्मिक स्वतंत्रता दोनों का सम्मान बना रहे। साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि यदि स्कूल इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं करेगा तो सरकार सख्त कदम उठाएगी। उन्होंने चेताया कि ऐसे मुद्दों को सांप्रदायिक विवाद का रूप देने से बचना चाहिए और इन्हें संस्थागत स्तर पर सहमति से सुलझाना चाहिए।

यह विवाद अपने आप में नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अलग-अलग हिस्सों में हिजाब को लेकर कई घटनाएँ सामने आई हैं, जिन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में स्वतंत्रता और अनुशासन की सीमाओं पर बहस छेड़ दी है। झारखंड के चतरा में जुलाई 2025 में दस छात्राओं ने आरोप लगाया था कि एक प्रिंसिपल ने जबरन उनके हिजाब उतरवा दिए। बाद में प्रशासन ने आरोपों को निराधार बताया, पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में इसी साल मई में एक छात्रा ने शिकायत की थी कि उसे हिजाब पहनने से रोका गया। बिजनौर में छात्राओं को स्कार्फ़ के रंग के निर्देशों का पालन न करने पर घर भेज दिया गया। वहीं कर्नाटक में एक सहायक प्रोफेसर पर आरोप लगा कि उसने छात्राओं को फील्ड ट्रिप के दौरान हिजाब पहनने के लिए बाध्य किया।

इन घटनाओं की श्रृंखला बताती है कि भारत में हिजाब का मुद्दा केवल कपड़े या परिधान का नहीं, बल्कि पहचान, समानता और संविधान में दर्ज स्वतंत्रता की भावना का है। यह सवाल अब बार-बार उठता है कि क्या स्कूल ड्रेस कोड के नाम पर किसी की धार्मिक अभिव्यक्ति को सीमित किया जाना उचित है, खासकर तब जब संविधान प्रत्येक नागरिक को अपनी आस्था और पहनावे की स्वतंत्रता देता है।

भारत की शिक्षा व्यवस्था हमेशा से धर्मनिरपेक्षता की मिसाल मानी जाती रही है। लेकिन जब हिजाब जैसे प्रतीक पर विवाद खड़ा होता है, तो यह सवाल खड़ा होता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है—क्या यह किसी धर्म को तटस्थ रूप से देखने का सिद्धांत है या धार्मिक पहचान को निजी क्षेत्र तक सीमित कर देने की कोशिश?

शिक्षाविदों का मानना है कि स्कूल अनुशासन के नाम पर जो एकरूपता लागू की जाती है, वह कभी-कभी संविधान में दिए गए अधिकारों से टकरा जाती है। वहीं, अभिभावकों और धार्मिक समूहों का तर्क है कि हिजाब पहनना व्यक्तिगत पसंद है और इसे शिक्षा के अधिकार से अलग नहीं किया जा सकता। देश के कई हिस्सों में अब यह बहस सड़कों, अदालतों और कक्षाओं से निकलकर घरों और सोशल मीडिया तक पहुँच चुकी है। लोग पूछ रहे हैं—क्या समानता का मतलब सबको एक जैसा दिखाना है या सबको अपनी पहचान के साथ बराबरी देना?

हिजाब की यह बहस अब केवल एक कपड़े की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता और संस्थागत अधिकारों के संतुलन की परीक्षा बन चुकी है। अदालतों के फैसले चाहे जो हों, लेकिन यह निश्चित है कि भारत की कक्षाओं में हिजाब का यह सवाल अब देश की संवैधानिक चेतना के केंद्र में है—जहाँ हर बच्चे को यह हक़ होना चाहिए कि वह अपनी पहचान और अपने विश्वास के साथ समान अवसर पा सके।

कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आतंक फिर बढ़ा: कारोबारी दर्शन सिंह की हत्या और पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर पर गोलियां बरसाईं

(जीएनएस)। टोरंटो। कनाडा में भारतीय गैंगस्टरों की दहशत लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार की रात लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दो अलग-अलग घटनाओं को अंजाम देकर पूरे कनाडा को हिला दिया। पहले कारोबारी दर्शन सिंह साहसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, और कुछ ही घंटों बाद पंजाबी सिंगर चन्नी नट्टन के घर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग की गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो गैंग ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार की है।

कनाडा पुलिस के अनुसार, दर्शन सिंह साहसी पर हमला देर रात सरे (Surrey) इलाके में हुआ। वह अपने ऑफिस से कार में लौट रहे थे, तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर फायरिंग कर दी। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हत्या के तुरंत बाद हत्यारे फरार हो गए, लेकिन पास के एक सीसीटीवी कैमरे में उनकी झलक कैद हो गई है।

कुछ ही घंटों बाद पंजाबी गायक चन्नी नट्टन के वैंकूवर स्थित घर के बाहर भी फायरिंग की गई। वहां मौजूद गार्ड्स और पड़ोसी बाल-बाल बचे। नट्टन उस वक्त घर में ही थे। गोलियों की आवाज़ सुनते ही उन्होंने पुलिस को कॉल किया। गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन घर की दीवारें और गाड़ी गोलियों

से छलनी हो गई।

इन घटनाओं के कुछ घंटे बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कनाडा स्थित सदस्य गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दोनों वारदातों की जिम्मेदारी ली। उसने लिखा—

"दर्शन सिंह को हमने इसलिए मारा क्योंकि वो नशे के कारोबार में लिप्त था और हमें धमकाने की कोशिश कर रहा था। हमने उससे मदद मांगी थी, लेकिन उसने हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया। उसे लगा हम सिर्फ नाम के गैंग हैं। अब सबको पता चल गया कि बिश्नोई गैंग क्या कर सकता है।"

ढिल्लन ने दूसरी पोस्ट में लिखा कि चन्नी नट्टन के खिलाफ उनकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन वह गायक सरदार खेहरा के करीबी हैं, जो "गैंग के दुश्मन" बताए गए हैं। पोस्ट में चेतावनी दी गई है कि "जो भी सिंगर या कलाकार सरदार खेहरा के साथ संबंध रखेगा, उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा।"

कनाडा पुलिस ने बताया कि ये दोनों घटनाएं "गैंगवॉर" का हिस्सा हैं, और बिश्नोई गिरोह के नेटवर्क को खत्म करने के लिए विशेष जांच टीम गठित की गई है। पुलिस ने टोरंटो, वैंकूवर और सरे में बिश्नोई गैंग से जुड़े करीब एक दर्जन संदिग्धों की गतिविधियों पर नज़र रखी है।

कनाडा सरकार पहले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को आतंकी संगठन (Terrorist Entity) घोषित कर चुकी है। सितंबर 2025 में जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि यह गिरोह कनाडा में "हिंसा, जबरन वसूली और धमकाने की संस्कृति" फैला रहा है। इस निर्णय के बाद इस गिरोह से जुड़ा कोई भी आर्थिक सहयोग, लेन-देन या सपोर्ट अब कानूनी अपराध है।

कनाडा पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले दो वर्षों में देश में दर्ज हुई हिंसक घटनाओं में से 40 प्रतिशत से अधिक में भारतीय मूल के गैंगस्टरों की संलिप्तता पाई गई है। इनमें गोल्डी बराड़, सुखदीप सिंह, लक्की पटियाल और अब गोल्डी ढिल्लन जैसे नाम सबसे ज्यादा सक्रिय हैं।

भारत में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के लिए यह गिरोह कनाडा में उसकी आर्थिक और आपराधिक गतिविधियों का "विदेशी मुख्यालय" बन चुका है। दरअसल, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बिश्नोई नेटवर्क के सदस्य कनाडा, यूके और दुबई में फैल गए हैं और वहीं से सोशल मीडिया के जरिये धमकी भरे वीडियो और बयान जारी करते हैं।

श्रीलंका सरकार का ऐतिहासिक फैसला: पूर्व राष्ट्रपतियों के सरकारी बंगले बनेंगे हाईकोर्ट, लंबित मुकदमों के तेजी से निपटारे की पहल

(जीएनएस)। कोलंबो। श्रीलंका सरकार ने न्याय व्यवस्था को सशक्त और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपतियों को दिए गए सरकारी बंगलों को अब हाईकोर्ट में परिवर्तित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य अदालतों में लंबित पड़े मुकदमों की सुनवाई को गति देना और आम जनता को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। विदेश मंत्री विजिता हेराथ ने मंगलवार को इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार चार नए हाईकोर्ट स्थापित करने जा रही है, जिनका संचालन उन सरकारी बंगलों से होगा जिन्हें हाल ही में पूर्व राष्ट्रपतियों से वापस लिया गया था।

विदेश मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। नए हाईकोर्ट कोलंबो के प्रतिष्ठित सिन्नामन गार्डन क्षेत्र में स्थित सरकारी बंगलों में बनाए जाएंगे। ये वही बंगले हैं जो वर्षों तक देश के शीर्ष नेताओं के आवास रहे हैं। मंत्री हेराथ ने कहा कि श्रीलंका में न्यायिक प्रणाली पर अत्यधिक बोझ है। अदालतों में लाखों मुकदमे वर्षों से लंबित हैं, जिससे आम नागरिकों को न्याय मिलने में बहुत समय लग रहा है। नई अदालतों के गठन से न केवल मामलों की संख्या

में कमी आएगी बल्कि न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी।

इस फैसले की पृष्ठभूमि में वह बड़ा बदलाव है जो श्रीलंका की संसद ने सितंबर महीने में किया था। संसद ने एक ऐतिहासिक बिल पारित कर पूर्व राष्ट्रपतियों के सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए थे। इस नए कानून के तहत अब उन्हें सरकारी बंगले, सुरक्षा गार्ड, सचिवालय, वाहन और मासिक भत्ते जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। केवल पेंशन की सुविधा बरकरार रखी गई है। इस कानून को श्रीलंका में 'राजनीतिक जवाबदेही की दिशा में बड़ा सुधार' माना गया।

कानून लागू होने के बाद पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे ने भी अपने सरकारी आवास को छोड़ दिया। उनका आलीशान बंगला कोलंबो के वीआईपी जोन सिन्नामन गार्डन में स्थित था। राजपक्षे 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे और बाद में प्रधानमंत्री पद भी संभाला। उनके कार्यकाल में श्रीलंका ने गृहयुद्ध समाप्त किया, लेकिन बाद में देश पर भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगे, जिनके चलते उनकी लोकप्रियता तेजी से घटी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, जिन बंगलों को अदालतों में बदला जा रहा है, उनमें आधुनिक सुविधाएं और पर्याप्त जगह उपलब्ध है, जिससे उन्हें न्यायिक उपयोग के लिए तैयार करना आसान रहेगा। चारों नए हाईकोर्ट में आधुनिक न्यायिक कक्ष, डिजिटल केस ट्रैकिंग सिस्टम और जनता के लिए ऑनलाइन सुनवाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय श्रीलंका के न्यायिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। एक ओर जहां यह कदम सत्ता में बैठे लोगों के विशेषाधिकारों को समाप्त कर 'समानता' का संदेश देता है, वहीं दूसरी ओर यह जनता को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में वास्तविक सुधार है। कानूनी विश्लेषकों के अनुसार, श्रीलंका में वर्तमान में लगभग 25 लाख मुकदमे विभिन्न अदालतों में लंबित हैं। इनमें से अधिकांश दीवानी और संपत्ति विवादों से संबंधित हैं। चार नए हाईकोर्ट के गठन से प्रति वर्ष लगभग 50,000 मामलों के निपटारे की गति बढ़ सकती है।

सरकार के इस फैसले को जनता के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। नागरिक संगठनों और मानवाधिकार समूहों ने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपतियों के सरकारी विशेषाधिकार समाप्त करना और उनके आवासों को न्यायिक संस्थानों में बदलना यह साबित करता है कि श्रीलंका एक अधिक जवाबदेह और पारदर्शी लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है।

कानपुर में दर्दनाक घटना: डरावने सपनों से परेशान छात्र आरव ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा— 'या तो खुद जान दे दो या परिवार को मार डालो'

(जीएनएस)। कानपुर। एक सिहरन पैदा कर देने वाली घटना ने पूरे कानपुर शहर को स्तब्ध कर दिया है। कोहना थाना क्षेत्र में रहने वाले 16 वर्षीय मेधावी छात्र आरव राज मिश्रा ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह हादसा तब हुआ जब उसके माता-पिता छठ पूजा के अवसर पर भागलपुर गए हुए थे और बहन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए बाहर गई थी। जब बहन घर लौटी और बार-बार दरवाजा खटखटाने के बाद कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तुड़वाया। अंदर का दृश्य देख सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई—आरव पंखे से लटका हुआ था।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। कमरे से एक छोटा सुसाइड नोट और मोबाइल फोन बरामद हुआ। मोबाइल में अंग्रेजी में लिखा एक विस्तृत नोट मिला, जिसमें आरव ने अपने भीतर चल रहे भय और मानसिक संघर्ष का वर्णन किया है।

नोट में लिखा है—

"मुझे बार-बार वही तीन-चार चेहरे सपनों में दिखाई देते हैं। वे मुझे कहते हैं—'या तो खुद जान दे दो या अपने परिवार को खत्म कर दो।' मैं अब इन सपनों से डरकर जी नहीं पा रहा हूं।"

आरव के पिता आलोक मिश्रा, जो एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, ने बताया कि उनका बेटा पिछले कुछ महीनों से डरावने सपनों की शिकायत कर रहा था। दीपावली की रात भी उसने बहन से कहा था कि उसे कुछ अनजान चेहरे दिखाई देते हैं, जो उसे नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हैं। परिवार ने इसे मानसिक तनाव या थकान समझकर नज़रअंदाज़ कर दिया, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह भय उसे आत्महत्या तक ले जाएगा।

कोहना थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि कमरे से कुछ चांदी की अंगूठियां, छल्ले और धार्मिक चिन्ह भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच फोरेंसिक टीम कर रही है। उन्होंने कहा कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि मामला किसी अंधविश्वास या मानसिक बीमारी से जुड़ा है या नहीं, लेकिन सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है।

आरव 'द जैन इंटरनेशनल स्कूल' का छात्र था और 11वीं कक्षा में पढ़ रहा था। हाईस्कूल में उसने 93 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे और राज्य स्तरीय स्विमिंग प्रतियोगिता में भी पदक जीत चुका था। शिक्षक और सहपाठी उसे एक होनहार, खुशमिजाज और मिलनसार छात्र बताते हैं। स्कूल में जब उसकी मौत की खबर पहुंची, तो पूरा परिसर गमगीन हो गया।

पड़ोसियों के अनुसार, आरव हमेशा मुस्कुराता रहता था और किसी से कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह घर में ज्यादा समय अकेले बिताने लगा था और मोबाइल पर कुछ लिखता रहता था।

पुलिस ने बताया कि मोबाइल का डेटा रिकवर कराया जा रहा है ताकि पता चल सके कि वह किसी मानसिक परामर्श समूह या ऑनलाइन चैटिंग में शामिल तो नहीं था। फोरेंसिक टीम ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यह मामला न केवल एक परिवार के लिए असहनीय त्रासदी है बल्कि यह सवाल भी उठाता है कि किशोरों में बढ़ती मानसिक अस्थिरता और भय को कैसे पहचाना जाए। आरव की मौत ने यह दर्दनाक सच्चाई उजागर कर दी है कि कभी-कभी 'डरावने सपने' भी एक वास्तविक और जानलेवा मानसिक संकट का रूप ले सकते हैं।

शहर में अब भी गम और सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग बस यही कह रहे हैं—इतना होनहार बच्चा, इतना उज्ज्वल भविष्य और इतनी भयावह मौत—क्या वाकई यह सिर्फ एक सपना था या उसके पीछे कोई गहरी दास्तान छिपी है, इसका जवाब अब पुलिस की जांच से ही मिलेगा।

'मेलिसा' बना मौत का सैलाब, जमैका में तबाही का खतरा – अमेरिका ने जारी किया भयावह VIDEO

(जीएनएस)। वाशिंगटन। धरती पर मौत का सैलाब बनकर उतरा हरिकेन 'मेलिसा' अब 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान बन चुका है। अटलांटिक महासागर से उठा यह तूफान कैरिबियाई देश जमैका की ओर तेजी से बढ़ रहा है, और इसकी विनाशकारी लहरें अब पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाने लगी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यह अब तक के सबसे खतरनाक तूफानों में से एक है, जिसकी तुलना 2017 के हरिकेन मारिया और 2005 के कैटरीना से की जा रही है।

अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान केंद्र (NHC) के मुताबिक, मेलिसा कैटेगरी-5 का सुपर हरिकेन है, जिसकी हवाएं 175 मील प्रति घंटा (लगभग 280 किमी/घंटा) की रफ्तार से चल रही हैं। समुद्र में लहरों की ऊंचाई 40 फीट तक पहुंच चुकी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसका केंद्र (Eye) लगभग 22 मील चौड़ा है और यह अपनी रफ्तार में और तेजी पकड़ रहा है। इस बीच, अमेरिकी वायुसेना की 'हरिकेन हंटर' टीम ने मंगलवार को एक बेहद जोखिम भरे मिशन के तहत इस तूफान के केंद्र में प्रवेश किया और इसके "दिल" का डेटा इकट्ठा किया। टीम ने जो वीडियो जारी किया है, उसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। वीडियो में तूफान के भीतर की भयावह शांति और चारों ओर फैला उफनता अंधड़ किसी महाप्रलय के दृश्य जैसा दिखता है।

जमैका में अब तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई घायल हैं। देश के तटीय इलाकों में हजारों घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने भावुक होते हुए कहा, "मैं घुटनों पर बैठकर भगवान से दया की प्रार्थना कर रहा हूं। हमारे देश के सामने एक कठिन और भयावह रात आने वाली है।"

हैती और डोमिनिकन गणराज्य में भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। कई गांवों में बिजली और संचार सेवाएं ठप हो चुकी हैं, जबकि राहत एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी तटीय इलाकों, खासकर फ्लोरिडा और लुइसियाना, में भी चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले दिनों में इस तूफान का परोक्ष असर महसूस किया जा सकता है। जलवायु विशेषज्ञों का कहना है कि हरिकेन मेलिसा केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि "मानवता के लिए चेतावनी" है। बढ़ते समुद्री तापमान और जलवायु परिवर्तन के कारण अटलांटिक महासागर में इस तरह के अत्यधिक शक्तिशाली तूफान अब सामान्य होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे "धरती की सबसे भयावह प्राकृतिक शक्तियों में से एक" कहकर संबोधित कर रहे हैं।

फिलहाल मेलिसा का रुख उत्तरी कैरिबियाई क्षेत्र की ओर है, और वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि अगर इसकी रफ्तार यही रही तो अगले 24 घंटे में यह जमैका और केमैन द्वीप के तटीय इलाकों को तबाह कर सकता है। राहत एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन को चौबीसों घंटे सतर्क रहने का आदेश दिया गया है।

यह तूफान एक बार फिर यह याद दिला रहा है कि प्रकृति के सामने मानव सभ्यता कितनी असहाय है — और जब समुद्र क्रोधित होता है, तो सारी तकनीक और ताकत भी बौनी पड़ जाती है।

नवसर्जन संस्कृति
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2063

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
नवसर्जन संस्कृति हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

परदेश में जलालत झेलती देश की जवानी

अमानवीयता की हद पार करती अमेरिका इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंसी के संवेदनहीन तौर-तरीकों का त्रास झेलते 54 हरियाणवी युवा शनिवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। सुनहरे सपनों की आस लिए अमेरिका गए इन युवाओं ने जिन त्रासदियों का सामना किया, वो उन युवाओं के लिये सबक भी है, जो अपनी योग्यता व क्षमता का मूल्यांकन किए बिना बस विदेश जाने की धुन में लगे रहते हैं। निस्संदेह, इन युवाओं ने बेहतर भविष्य के लिये रिस्क लेने का जज्बा तो दिखाया, लेकिन एजेंटों के छलावे के चलते डंकी रूट पर फिसल गए। इन युवाओं को इस बात का भान नहीं रहा कि घोर दक्षिणपंथी रुझान वाले ट्रंप के शासन में प्रवासियों के साथ कैसी क्रूरता व भेदभाव किया जा रहा है। जिसके चलते उनके साथ अमेरिका में अपराधियों जैसा सुलूक किया है। उन्हें जेल और अपराधियों के लिये बने कैंपों में रखा गया। युवाओं ने आरोप लगाया कि जेलों में गर्मी में हीटर और सर्दी में एसी चलाकर रखा जाता था। शाकाहारियों को मांस दिया जाता था और न खाने पर सिर्फ सूखी रोटी। खेत बेचकर-कर्ज लेकर उज्ज्वल भविष्य के लिये अमेरिका गए युवा अपराधियों की तरह स्वदेश लौटे। समाचार माध्यमों में प्रकाशित चित्रों में इन हताश युवाओं को अपराधबोध से ग्रसित देखा गया। विडंबना देखिए कि कई युवा अपना खेत बेचकर और चालीस-पचास लाख एजेंट को देकर विदेश गए, लेकिन डंकी रूट में धकेल दिए गए। उस खतरनाक रास्ते पर जहां हर पल मौत का खतरा बना रहता है। परिवार वालों को इस बात का सुकून जरूर होगा कि कम से कम उनके बच्चे सकुशल तो घर लौट आए है। वो बात अलग है कि इन युवाओं को अपने असफल प्रयास का मलाल जीवनपर्यंत सालता रहेगा। कुछ युवा इससे अवसादग्रस्त हो सकते हैं। कुछ हताश युवा भटकाव की राह में गुजर सकते हैं। निश्चय ही यह घटनाक्रम इन युवाओं के लिये एक त्रासदी से कम नहीं रहेगा। सुखमय जीवन की आस ने नारकीय जीवन जीने को मजबूर कर दिया। वे बेड़ियों में देश लौटे। बहरहाल, इन युवाओं की अपमानजनक वापसी कई ज्वलंत सवालों को भी जन्म देती है। यह हमारी नीति-नियंताओं की विफलता ही है कि हम युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं दे पा रहे हैं। हम कहते नहीं थकते कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। सवाल यह है कि इस युवा शक्ति को दिशा देने के लिये हमने क्या किया? तमाम प्रलोभन व लोकलुभावने वादे करने वाले राजनीतिक दलों की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना क्यों नहीं होती? सिर्फ चुनाव आने पर करोड़ों रोजगार देने के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बावजूद वे पूरे नहीं होते। दोष हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी है जो डिग्री तो देती है, लेकिन रोजगार की गारंटी नहीं देती। दोष हमारी युवा पीढ़ी की उस मानसिकता का भी है जो सिर्फ नौकरी और उसमें भी सरकारी नौकरी को प्राथमिकता देती है। निजी क्षेत्र भी सिर्फ मुनाफे को प्राथमिकता देता है और तकनीक के जरिये रोजगार के अवसरों में कटौती को प्राथमिकता देता है। ऐसे देश में, जहां आबादी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमें श्रम प्रधान उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जिसमें अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। कायदे से देश में बेरोजगारी का ग्राफ देखते आने वाले दशकों के लिये रोजगार का रोडमैप बनना चाहिए। लेकिन सत्ता भी सस्ती लोकप्रियता वाले कामों के जरिये अपना वोट बैंक सुधारने में लगी रहती है। यहां सवाल युवाओं व अभिभावकों की सोच का भी है, जो खेत बेचकर बेटे को विदेश भेजने की फिराक में रहते हैं। जितना पैसा उन्होंने विदेश भेजने वाले एजेंटों को दिया, उसमें क्या वे स्वरोजगार नहीं कर सकते थे? माना कि आज खेती-किसानी युवाओं को नहीं लुभाती, लेकिन वे इस खेत पर गैर परंपरागत खेती व फल-फूल आदि नकदी फसलों के विकल्प तो तलाश सकते हैं। सवाल हमारी प्रवर्तन एजेंसियों पर है कि क्यों युवाओं को विदेश भेजने वाले एजेंटों पर कार्रवाई नहीं करती, जो लाखों रुपये लूटकर इन्हें नर्क में धकेल देते हैं। वापस आए इन युवाओं के जरिये उन तक पहुंचा जा सकता है।

संयम आधारित हो नये दौर की शासन कला

> भारत की रणनीतिक स्वायत्तता विभाजित दुनिया का आधार बिंदु है। ऐसे समय में जब दुनिया युद्धों की आग में झुलस रही है, हमारे गणतंत्र ने सिद्धांतों पर युद्ध खत्म करने का अनुशासन दर्शाया है। ढाका से लेकर कारगिल व ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय गणतंत्र की जीत सभ्यतागत रही है।

युद्ध कभी-कभार ही वहां खत्म होते हैं जहां वे थमते हैं; जहां वे विराम लेते हैं वहां से अनुपात का आगाज़ होता है। वर्साय से लेकर गाजा तक, बगदाद से कीव तक, हर अधूरा युद्ध वही सबक दोहराता है: बिना संयम की जीत अपने ही विनाश के बीज बोती है। जब जीत अपमान में बदल जाए, तब शांति भरभरा कर गिर जाती है। भारत लंबे समय से इस सच्चाई को जानता है। ढाका से लेकर कारगिल व ऑपरेशन सिंदूर तक, भारतीय गणतंत्र की जीत सभ्यतागत रही है, युद्धविराम थकान से नहीं अपितु दूरदर्शिता से रोक लेने की क्षमता। संयम का अर्थ पीछे हटना नहीं ; यह एक फैसला होता है, विवेक के साथ साहस का, अनुपात संग शक्ति का। अंत भला हो, यह कमान का सबसे मुश्किल काम है।

अपरिमेय जीत का जाल : जैसे कि दुनिया के महाद्वीपों और समुदायों में खून बह रहा है, संयम की बात कहीं नहीं हो रही। युद्ध बेवजह जारी रहते हैं, और शांति का कोई नामलेवा नहीं। इस नैतिक शून्य में, भारत की आनुपातिक संतुलन की विरासत एक गुण से कहीं ज़्यादा है, यह अतिरेक के युग के लिए प्रति-आख्यान बन जाती है। अपरिमेय जीत सत्ता का सबसे पुराना जाल है। वर्साय ने हिटलर को जन्म दिया; इराक के जातीय बंटवारे ने आईएसआईएस पैदा की। बिना सोचे-समझे बदला लेने की प्रवृत्ति सिर्फ वर्दी बदलती है, दुश्मनी नहीं। पूर्ण विजय की तलाश अक्सर अगली पीढ़ी की पूर्ण हार तय करती है। भारत का अनुशासन सिद्धांतों पर युद्ध खत्म करने में है, न कि तालियों की खातिर।

विघटन पैदा करने वालों को चुनौती : वर्तमान विश्व व्यवस्था के रचनाकार, जो गठबंधन को आज्ञाकारिता के बराबर मानते हैं, जिस विघटन को वे अब कोस रहे हैं वह खुद उन्होंने पैदा किया। जो लोग स्वायत्तता की आलोचना अलग-थलग पड़ जाने या तटस्थता रखने के रूप में करते हैं, उनके लिए जवाब सरल है: गुटों की वफादारी विफल रही। भारत का अनुशासन

महज घरेलू गुण नहीं; यह शक्ति के विफल मॉडल को चुनौती देता है, एक दबाव रहित आमूल-चूल बदलाव पेश करता है, जिसमें स्वायत्तता व संयम रणनीतिक पसंद के उच्चतम रूप बन जाते हैं। आधुनिक शक्ति का व्याकरण : संयम सिर्फ विरासत बनकर नहीं रह सकता। आज शक्ति प्रयोग न केवल हथियारों से बल्कि एल्गोरिदम, वित्त और इन्फ्लुएंस के जरिये किया जाता है। राज्य-व्यवस्था का व्याकरण बदल गया है। सप्लाई चेन घेराबंदी की रस्सियां हैं, डेटा नया रणक्षेत्र है, और सबसे आगे है कहानी गढ़कर फैलाने की होड़। आगामी युद्ध घोषित रूप में न होकर सहेज कर पाली खुन्नस है, जो धारणा, सटीकता और धैर्य के जरिये लड़े जाएंगे। जो देश अंत बढ़िया कर सकेगा वही लंबा टिक पाएगा। भारत के लिए चुनौती दोहरी है: सदी की रफ़्तार से कदम मिलाकर अपना सभ्यतागत स्वभाव कायम रखना। सिद्धांत को तैयारी संग, नैतिकता को फुर्ती के साथ, और धैर्य को सटीकता से जोड़ना होगा। संयम की कला तकनीक, कूटनीति और संचार के साथ पिरोनी होगी। रणनीतिक स्वायत्तता का मरहम – जब पी-5 वीटो से पंगु हो जाता है, संयुक्त राष्ट्र निष्प्रभावी हो जाता है और लहु-लुहान दुनिया में खून बहना जारी रहता है। व्यापार एक हथियार बन गया और शांति पुरस्कार की चाहत रखने से पहले काबिलियत का ढिंढोरा पीटने वाले प्रायोजक ढूंढ़े जा रहे हैं; तब फिर किससे उम्मीद की जाये? कोई नहीं। ऐसे ही हालात में भारत की सभ्यतागत नैतिकता की जरूरत है, हुक्म चलाने के लिए नहीं, बल्कि मिसाल पेश करने को। यह दिखाने के लिए कि ताकत को परिभाषित करने के लिए दूसरे पर हावी होने की ज़रूरत नहीं; वह संयमित राष्ट्र जो सीना तान चले, अभी भी तूफान को थाम सकता है। विभाजित दुनिया में यह रणनीतिक स्वायत्तता है, सिद्धांत परक तीसरी राह, जो गुटीय राजनीति से दूर रहे, ऐसा मरहम जो तारीफ चाहे बिना घाव भर दे।

संयम की पुनर्कल्पना : नतीजों पर महारत पाने के बाद संयम को अब संदर्भ में सिद्धहस्तता हासिल करनी होगी। यह वहां से शुरू होता है जहां शक्ति प्रयोग खत्म होता है और ज़िम्मेदारी शुरू होती है। यह दूरदर्शिता के जरिए व्यक्त अनुपात और दृढ़ विश्वास से दर्शाया आत्मसंयम है। शासन उद्वेग, शक्ति और प्रयोजनवश झूठ से परे होता है, उकसाने पर भी सटीकता से काम करने का अनुशासन, बिना किसी की नकल किए व्यवस्था बनाए रखना, अलग-थलग पड़े बगैर पहचान कायम रखना। सशस्त्र बलों ने लंबे समय से इस अनुशासन का पालन किया, ढाका में युद्धविराम से लेकर सिंदूर सिद्धांत तक: शांत रहकर तैयारी, बिना प्रचार की सटीकता, और अत्याचार से रहित शक्ति। टकराव पर वार्ता को प्राथमिकता देकर भारतीय कूटनीति ने भी इसे अपनाया। अगला सीमाक्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जहां तकनीक पारदर्शिता की सेवार्थ हो न कि अत्याचार के हितार्थ। जो गणराज्य अपने एल्गोरिदम को मानवीय बना सकता है, वह न केवल शक्ति बल्कि विश्वास भी अर्जित करेगा। डिजिटल क्षेत्र में गति को सच्चाई के साथ संतुलित करने की भारत की सहज वृत्ति, उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक देन हो सकती है।

शांति की परीक्षा: ऐसे संतुलन के लिए निगरानी चाहिये। दुनिया बिखरी पड़ी है, क्षेत्रों में उथल-पुथल है; पुरानी निष्ठाएं बदल रही हैं, और चीन का चुपके से प्रवेश शांति के मुखौटे के पीछे छिपा है। गढ़ी गई ऐसी शांति में, कूटनीति तले धोखेबाज़ी चलती है। यहीं पर संयम को सिर्फ इंतज़ार न करके विचार करना होगा, जहां आत्म संयम स्पष्टता से मेल खाता है। हम अपने इलाके की वापसी न तो ज़्यादा चिल्लाकर, न ही कठोर गुट में शामिल होकर पा सकते हैं, बल्कि उनसे ज़्यादा समय टिके रहकर, साझेदारी और शांतचित्त रहकर ले पाएंगे। उपद्रव के युग को दरकार है दक्ष साहस की: एक तेज़ गति वाली दुनिया में धीमे रहकर सोचने की क्षमता, जहां एल्गोरिदम गति पर जोर देता है वहां स्थिर खड़े रहने की क्षमता। जब आवाज़ तेज़ हो, तो संयम आवेश में आकर नहीं आवृत्ति में अपनी बात कहे।

विश्वास हासिल करना : शासन प्रबंधन की नई सीमा - आधुनिक शासनकला का असली पैमाना उसकी प्रतिक्रिया की गति से नहीं, बल्कि अपने आवेग पर नियंत्रण में महारत है। जो गणतंत्र समझदारी के बदले तेज़ी चुन लेगा, लड़खड़ा जाएगा; ताकत शांत उद्देश्य में है, उस अनुशासन में है जिसका गुस्से पर नियंत्रण है। मनोवैज्ञानिक सीमा ही अब असली ताकत का कार्यक्षेत्र है। भारत का लचीलापन एक विशाल और मुखर समाज से आता है जहां असहमति धारणा को मजबूती देती है और लोकतंत्र की गूंज गणतंत्र के रास्ते को स्थिर रखती है: विविधता में एकता। सिंदूर ने दिखाया : संयम के साथ तैयारी, संकल्प के साथ सभ्यता। यही रणनीतिक संदेश है, और नैतिक भी। अगला अध्याय : यह कोई संधि या समझौते वाला नहीं होगा; यह शक्ति को खुद-ब-खुद नर्म करेगा। यह उन लोगों का होगा जो बिना धमकाए नवपरिवर्तन कर सकें, हावी हुए बगैर रक्षा कर सकें, और उनका जो बिना दिखावे के नेतृत्व कर सकें। इसी संतुलन में भविष्य की शांति का खाका छिपा है। यह निवारण के व्याकरण में भारत का योगदान होगा।

आखिरी विचार : न डगमगाने वाली लौ - जब दुनिया शांत हो, तो संयम को हिचकिचाहट और स्वायत्तता को विरक्ति समझ लिया जाता है। लेकिन जब दुनिया जल रही हो, जैसा कि फिलहाल हो रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर जैसे पलों में भी एक सभ्यतागत शोकगीत के सुर सुनने को मिले, तब शक्ति का असली रूप सामने आता है। शांति पुरस्कारों की होड़ में, जब पराजित उस चीज़ श्रेय लेने में हड़बड़ी में हो, जो उसने किया ही नहीं, तब भारत सबसे अलग खड़ा होता है। इसका सभ्यतागत संयम और रणनीतिक स्वायत्तता महज विरासत नहीं; वे इसके स्थायी चरित्र को परिभाषित करती दो ताकतें हैं, एकमात्र वे हाथ जो आग भड़काए बगैर ज्वाला को थामे रखने में सधे हैं।

प्रेरणा

भविष्य की कला — रवींद्रनाथ ठाकुर की दृष्टि में छिपे एक महान कलाकार की पहचान

शांतिनिकेतन का वातावरण हमेशा से कला, संगीत और साहित्य की आत्मा से भरा रहा है। वहां हर कोना रचनात्मकता की गूंज से जीवंत था। एक दिन वहीं के विद्यालय में एक चित्रकला प्रदर्शनी लगी थी। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए चित्र सजे हुए थे — कोई प्रकृति का सौंदर्य उकेर रहा था, कोई मनुष्य की भावनाओं का, तो कोई कल्पना के आकाश को रंगों में पिरो रहा था। दर्शक दीर्घा में स्वयं विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर आए थे। उनके कदम धीमे थे, लेकिन दृष्टि अत्यंत सजग — वे प्रत्येक चित्र को ध्यान से देख रहे थे, मानो हर रेखा, हर रंग से संवाद कर रहे हों। चित्रों की भीड़ में अचानक उनकी नजर एक कोने में रखे एक साधारण-से चित्र पर पड़ी। वह किसी महंगे फ्रेम में नहीं था, न ही उसमें रंगों का चमत्कार दिखता था। बस एक पेड़ था, उसके पीछे उगता हुआ सूरज और आकाश में उड़ता हुआ एक छोटा-सा पक्षी। यह चित्र देखने में तो सामान्य था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जिसने गुरुदेव का ध्यान रोक लिया। उन्होंने उस चित्र के सामने कुछ क्षण मौन होकर देखा, फिर धीरे से शिक्षक से पूछा, "यह चित्र किसने बनाया?"

शिक्षक ने सहज स्वर में कहा, "गुरुदेव, यह हमारे गांव से आया एक नौ साल का बालक है। अभी सीख रहा है, इसलिए इसका चित्र साधारण है।" रवींद्रनाथ ने मुस्कराकर कहा, "नहीं, यह चित्र साधारण नहीं है। देखो, इस

पेड़ की रेखाओं में जीवन है, इस सूरज में आशा है और इस पक्षी में स्वतंत्रता की चाह। इसकी आंखों में डर नहीं है — और यही कला की पहली निशानी है।"

उन्होंने अपनी जेब से कलम निकाली, और उस चित्र के नीचे अपने हाथों से लिखा — "इस चित्र में भविष्य बोल रहा है।"

शिक्षक उस समय मुस्कराए, लेकिन शायद वे नहीं समझ पाए कि गुरुदेव की दृष्टि कितनी गहरी थी। समय बीतता गया। वही बालक, जो कभी गांव से शांतिनिकेतन आया था, बड़ा होकर वही भविष्य बना जिसकी झलक रवींद्रनाथ ने देखी थी। वह था बिनोद बिहारी मुखर्जी — भारतीय आधुनिक चित्रकला का वह नाम, जिसने बाद में शांतिनिकेतन के कला विभाग को नई दिशा दी, और रवींद्रनाथ ठाकुर के संग्रहालयों की कलात्मक सज्जा का कार्य संभाला। बिनोद बिहारी मुखर्जी की दृष्टिहीनता भी उनकी सृजनशक्ति को नहीं रोक सकी। उनके चित्रों में वही ऊर्जा, वही निडरता और वही स्वतंत्रता का भाव था, जो बचपन में उस एक साधारण चित्र में दिखा था।

रवींद्रनाथ ठाकुर की वह टिप्पणी केवल एक वाक्य नहीं थी, वह एक दृष्टि थी — एक ऐसी दृष्टि जो हर बालक के भीतर सोई हुई संभावनाओं को देख सकती थी। "इस चित्र में भविष्य बोल रहा है" — यह पंक्ति इस बात का प्रमाण बन गई कि सच्ची कला का मूल्यांकन सुंदरता से नहीं, बल्कि भावना, साहस और आत्मा की गहराई से होता है।

शांतिनिकेतन की उस प्रदर्शनी में रचा गया वह क्षण केवल एक चित्र का मूल्यांकन नहीं था, बल्कि वह भारतीय कला इतिहास के एक स्वर्ण अध्याय की शुरुआत थी — जहां एक गुरु ने एक शिष्य में भविष्य देखा, और वह भविष्य स्वयं कला बन गया।

जब डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की कटुता कम होगी तो भारत व अन्य देश भी लाभान्वित होंगे!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आसियान बैठक के बहाने हुई मुलाकात में मुख्यतः व्यापारिक तनाव को कम करने और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर गम्भीरता पूर्वक चर्चा हुई। बताया जाता है कि दोनों देशों ने टैरिफ, निर्यात नियंत्रण, कृषि उत्पादों के व्यापार, और फेंटेनाइल तस्करी जैसे अहम मसलों पर बातचीत की। खास बात यह रही कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने चीन पर फेंटेनाइल की तस्करी का आरोप लगाया, जिसे ट्रंप ने अपनी बातचीत का मुख्य मुद्दा बनाया।

इसके अलावा, रूस से तेल खरीद, अमेरिकी किसानों से आयात, व्यापार असंतुलन जैसे विषय भी बैठक में उठाए गए। यही वजह है कि दोनों देशों ने व्यापार युद्ध को खत्म करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए बुनियादी सहमति पर पहुंचने की कोशिश की है। गौरतलब है कि दोनों देशों ने ही मुलाकात की पुष्टि की है, और यह माना जा रहा है कि संबंधों में सुधार की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम है।

अंतरराष्ट्रीय विश्लेषकों के मुताबिक, जहां ट्रंप ने आने वाली पहली बातचीत में फेंटेनाइल मुद्दा उठाने की बात कही है, वहीं शी जिनपिंग ने भी वार्ता को रचनात्मक बताया। अगली मुलाकात आगामी 30 अक्टूबर को साउथ कोरिया के बुसान में होगी, जहां एपीईसी सम्मेलन भी आयोजित हो रहा है। इस बैठक में ताइवान और हांगकांग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें ट्रंप ने लोकतंत्र समर्थक नेता जिमी लाई की रिहाई का मुद्दा उठाने की बात कही है।

कुल मिलाकर, यह मुलाकात अमेरिका-चीन के बीच बढ़ते व्यापारिक और राजनीतिक तनाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है जो वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं, ट्रंप और शी जिनपिंग की आसियान बैठक में हुए व्यापार समझौते के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:-

पहला, व्यापार युद्ध विराम विस्तार: दोनों देशों ने व्यापार युद्ध विराम समझौते को विस्तारित करने पर सहमति बनाई, जिससे व्यापारिक तनाव कम होगा।

दूसरा, टैरिफ वार टालना: अमेरिका ने 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी की थी, जिसे समझौते के तहत टाला गया। चीन ने अमेरिकी टैरिफ और निर्यात प्रतिबंधों पर सौहार्दपूर्ण वार्ता की सहमति दी।

तीसरा, फेंटेनाइल नियंत्रण: व्यापार के अलावा, फेंटेनाइल तस्करी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई, जिसे अमेरिकी पक्ष ने गंभीरता से उठाया।

चतुर्थ, निर्यात नियंत्रण: चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स और अन्य प्रमुख विनिर्माण इनपुट पर निर्यात नियंत्रण पर बातचीत हुई, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला स्थिर रह सके।

पंचम, कृषि एवं तेल आयात: अमेरिकी किसानों से फसल खरीद और रूस से तेल खरीद को लेकर भी बहस हुई, जो दोनों देशों के बीच व्यापार असंतुलन को कम करने में मदद करेगी।

षष्टम, वैश्विक आर्थिक स्थिरता: दोनों नेताओं ने वैश्विक बाजारों में स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई।

समझा जाता है कि इस समझौते से अमेरिका-चीन के व्यापारिक विवादों में कमी आने और वैश्विक आर्थिक दुष्प्रभावों को कम करने की उम्मीद है। इसप्रकार से यह बैठक रणनीतिक आर्थिक सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, ट्रंप और शी जिनपिंग ने टैरिफ और निर्यात नियंत्रण पर महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि अमेरिका ने चीन पर 100 प्रतिष्ठित टैरिफ लगाने की योजना को अब टाल दिया है, जिससे बड़े टैरिफ युद्ध की आशंका कम हो गई है। दोनों देशों ने चीन की दुर्लभ पृथ्वी (Rare Earth) मृदा पदार्थों के निर्यात नियंत्रण को कुछ समय के लिए स्थगित करने पर सहमति जताई है। इस समझौते को लेकर दोनों पक्षों की बातचीत को "रचनात्मक और गहन" बताया गया है।

वहीं, चीन ने भी यह खुलकर माना है कि निर्यात नियंत्रण को लेकर प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन में स्थिरता बनी रहे। इस कदम से व्यापार में संतुलन आएगा और दोनों देशों के बीच तनाव कम होगा। इसके साथ ही, व्यापार युद्ध को खत्म कर आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है।

बता दें कि इस सबके पीछे प्रमुख कारण अमेरिका द्वारा 1 नवंबर से नए 100 प्रतिशत टैरिफ लगाए जाने की धमकी थी, जिसे चर्चा के बाद टाला गया। दोनों नेताओं की मुलाकात में इन मुद्दों को लेकर गंभीर और सकारात्मक बातचीत हुई है, जिससे व्यापारिक संबंध बेहतर हो सकेंगे।

इसलिए, टैरिफ टालने और निर्यात नियंत्रण पर सहमति ने आगामी व्यापारीय विवादों को कम करने का मार्ग प्रशस्त किया है और एक संतुलित, स्थिर व्यापारिक वातावरण बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है।

इन बातों से स्पष्ट है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के वैश्विक मायने बड़े और कई पक्षों से देखे जा सकते हैं। कुल मिलाकर यह बैठक अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे व्यापारिक तनाव, विशेषकर टैरिफ विवाद पर समाधान की उम्मीद जगाती है। बताया जाता है कि आगामी 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया में दोनों देश के नेता मिलेंगे और अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए 155 प्रतिशत से अधिक टैरिफ के मुद्दे पर बातचीत करेंगे, जिससे वैश्विक व्यापार में स्थिरता आ सकती है।

इसके अलावा, इस मुलाकात में ताइवान की स्थिति, यूक्रेन युद्ध, और फेंटेनाइल की तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी चर्चा होगी। ट्रंप ने कहा है कि उनका उद्देश्य किसानों के हितों का संरक्षण करते हुए दोनों देशों के बीच व्यावहारिक और पूर्ण समझौता करना है। कहना न होगा कि यदि यह वार्ता सफल होती है, तो इससे न केवल अमेरिका और चीन के द्विपक्षीय संबंध सुधरेंगे, बल्कि वैश्विक बाजारों में भी स्थिरता आएगी और ब्रिक्स देशों जैसे विकासशील देशों की स्थिति पर असर पड़ेगा।

अभियान

शिव पुराण में बताई गई विशेष पूजा विधि से मिलता है भोलेनाथ का आशीर्वाद, हर इच्छा होती है पूरी

प्राचीन काल में जब महर्षियों ने सूतजी से भगवान शिव की पूजा की विधि पूछी, तब उन्होंने कहा कि जो भी भक्त शिवपुराण में वर्णित इस विशेष पूजा-विधान का पालन करता है, उसकी हर मनोकामना शिव कृपा से पूरी होती है। यह पूजा-विधान इतना प्रभावी और रहस्यमय है कि इसके माध्यम से भक्त न केवल सांसारिक सुख प्राप्त करता है, बल्कि अंततः मोक्ष का अधिकारी बनता है।

सूतजी ने बताया कि यह वही प्रश्न है, जो एक समय ब्रह्माजी से नारदजी ने पूछा था। ब्रह्माजी ने कहा था कि भगवान शिव की पूजा में प्रयुक्त होने वाले फूल, पत्ते और सामग्री का प्रत्येक तत्व अपने-आप में एक दिव्य शक्ति रखता है। बेलपत्र, कमलपत्र, शतपत्र, और शंखपुष्प जैसे पवित्र पुष्प शिव पूजन में विशेष फलदायी माने जाते हैं। बेलपत्र को तो स्वयं भगवान शिव का प्रिय कहा गया है। इसके माध्यम से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह न केवल देवता की प्रसन्नता का प्रतीक है, बल्कि मन की पवित्रता का भी सूचक है।

शिवपुराण में कहा गया है कि बीस कमल का एक प्रस्थ और सहस्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। सोलह पल का एक प्रस्थ तथा दस टंक का एक प्रस्थ माना गया है। जब इस माप के अनुसार पूजन सामग्री चढ़ाई जाती है, तब सकाम पूजा करने वाला व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है और निष्काम भाव से पूजा करने वाला शिवस्वरूप बन जाता है। जो व्यक्ति दस करोड़ पार्थिव लिंगों की पूजा करता है, वह राज्य और समृद्धि का भागी होता है।

हे मुनिवर — शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर अखंड जल की धार, चंदन, पुष्प और अक्षत (चावल) अर्पित करना चाहिए। प्रत्येक ऋतु में प्रति मंत्र एक बेलपत्र, शतपत्र या कमल चढ़ाने का विधान है। शंखपुष्पों से विशेष विधि से पूजन करने पर भक्त को दोनों लोकों में सर्वकाम सिद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद दीप, धूप, नैवेद्य, आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार कर क्षमा-प्रार्थना और विसर्जन करना चाहिए। यह सांगोपांग पूजन केवल भोग और राज्य ही नहीं देता, बल्कि रोगों से मुक्ति का भी मार्ग है। शिवपुराण में विस्तार से बताया गया है कि कौन-सी मनोकामना के लिए कितने पुष्प चढ़ाने चाहिए —

रोगों से मुक्ति के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या प्राप्ति के लिए 25 हजार कमल पुष्प, विद्या प्राप्ति के लिए इसका आधा, वाणी के लिए घृत से पूजा, मारण हेतु एक लाख पुष्प, मोहन के लिए उसका आधा, और राजा के वशीकरण हेतु दस लाख पुष्प चढ़ाने चाहिए। यश के लिए भी इतना ही पुष्प अर्पण करना चाहिए, ज्ञान के लिए एक करोड़ पुष्प, और शिव-दर्शन की अभिलाषा रखने वाला इससे आधे पुष्पों से पूजन करे। कार्य-सिद्धि के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पांच लाख बार जप करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं।

जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा रखता है, उसे कुशा से शिवजी का पूजन करना चाहिए। आयु की कामना करने वाला एक लाख दूर्वा चढ़ाए, पुत्र की इच्छा वाला लाल डंडी वाले पुष्प अर्पित करे। तुलसी से पूजन करने पर भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। प्रताप बढ़ाने के लिए आक का फूल, शत्रुनाश के लिए एक लाख पुष्प चढ़ाने चाहिए।

शिवपुराण में कहा गया है कि ऐसा कोई फूल नहीं जो शिवजी को अप्रिय हो, केवल चंपा और केतकी को छोड़कर। चावल से पूजन करने का भी विधान बताया गया है। अखंडित चावल शिवजी को अत्यंत प्रिय हैं। इनका उपयोग भक्तिपूर्वक करना चाहिए। एक लाख, छह प्रस्थ, तीन प्रस्थ या दो पल के अनुसार चावल चढ़ाए जा सकते हैं। इन पर गंध, श्रीफल और पुष्प रखकर दीप-धूप करें। इसके बाद दो रुपए या दो माशे की दक्षिणा दें और 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। यह कर्म पूर्ण फलदायक माना गया है। शिवपुराण में आगे कहा गया है कि एक लाख पल तिल चढ़ाने से महापापों का नाश होता है। 11 पल अर्थात चौसठ मासा एक लाख तिल के बराबर माने गए हैं। हितकामना के लिए पूर्ववत् पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। एक लाख या आठ प्रस्थ जौ चढ़ाने से स्वर्ग और सुख की प्राप्ति होती है।

यदि घर में कलह, विवाद या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो, तो शिवजी पर जल की अखंड धारा चढ़ाना चाहिए। इससे परिवार में शांति आती है। शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो, तो शिवलिंग पर तेल की धारा चढ़ानी चाहिए। शहद से पूजा करने वाला व्यक्ति यक्षराज की उपमा प्राप्त करता है। गन्ने के रस से शिवपूजन करने से जीवन में आनंद और मंगल की वृद्धि होती है, और गंगाजल की धारा से पूजन करने वाला भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। इसकी संख्या दस हजार बताई गई है, जिसके बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने का विधान है।

अंत में सूतजी ने कहा — "हे मुनिश्वर! जो भी भक्त शिव, पार्वती और स्कंद सहित भगवान महेश की इस विधि से पूजा करता है, वह अपने पुत्र-पौत्रों सहित समस्त सांसारिक सुखों का भोग कर अंततः महेश्वर लोक का अधिकारी बनता है।"

शिवपुराण में वर्णित यह पूजा-विधान न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह मनुष्य के कर्म, श्रद्धा और भक्ति का शुद्धतम रूप भी है। जो इसे निष्ठा, विश्वास और नियमपूर्वक करता है, उस पर भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं, और उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है — क्योंकि शिव कृपा वही पाता है, जो भक्ति में संपूर्णता और समर्पण से लीन होता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

गुजरात BJP के लिए नई चुनौती बने AAP विधायक चैतर वसावा, जेल से निकलने के बाद आदिवासी बेल्ट में उभरे जननेता, लोकप्रियता ने चौंकाया सत्तारूढ़ दल

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात की राजनीति में नया समीकरण आकार लेता दिखाई दे रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने रिकॉर्ड जीत दर्ज करते हुए लगातार सातवीं बार सत्ता हासिल की थी, लेकिन अब उसी गुजरात में आम आदमी पार्टी का एक विधायक सत्तारूढ़ दल के लिए सिरदर्द बन गया है। यह नाम गोपाल इटालिया का नहीं, बल्कि डेडियापाड़ा से चुने गए विधायक चैतर वसावा का है — जो इस समय गुजरात की आदिवासी राजनीति का सबसे उभरता हुआ चेहरा बन चुके हैं।

चैतर वसावा हाल ही में वडोदरा की सेंट्रल जेल से रिहा हुए हैं। उनकी रिहाई के बाद से जिस तरह से जनसमर्थन उमड़ रहा है, उसने न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस तक को चौंका दिया है। दाहोद से लेकर छोटा उदेपुर तक उनके कार्यक्रमों में भारी भीड़ उमड़ रही है। उनके भाषणों में आदिवासी अस्मिता, किसानों की समस्याएँ और शासन के खिलाफ मुखर तेवर साफ झलकते हैं।

वसावा को ढाई महीने बाद जब गुजरात हाईकोर्ट से जमानत मिली थी, तब अदालत ने उन्हें अपने विधानसभा क्षेत्र डेडियापाड़ा जाने पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस पाबंदी के बावजूद वसावा ने अपनी राजनीतिक रणनीति को सीमित नहीं होने दिया। वे अब पूरे दक्षिण और मध्य गुजरात की आदिवासी पट्टी में घूम रहे हैं और "गुजरात जोड़ो" अभियान के माध्यम से लोगों से सीधा संवाद स्थापित कर रहे हैं।

हाल ही में छोटा उदेपुर में आयोजित 'गुजरात जोड़ो पदयात्रा' में उमड़े जनसैलाब ने उनके बढ़ते प्रभाव का संकेत दिया। इस दौरान वसावा ने कहा, "गुजरात के कोने-कोने से हजारों लोग BJP की तानाशाही और भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। यह आंदोलन अब रुकने वाला नहीं है। आदिवासियों के हक, किसानों के मुआवजे और स्थानीय युवाओं की बेरोजगारी का जवाब सरकार को देना होगा।"

वसावा न केवल आप के सदस्यता अभियान का चेहरा बने हुए हैं, बल्कि विधानसभा में विधायक दल के नेता के तौर पर सरकार पर तीखा हमला भी कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष अगस्त में गुजरात सरकार ने अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए 319 करोड़ रुपये और बाद में 1415 करोड़ रुपये के मुआवजे की घोषणा की थी, लेकिन आज तक किसानों को यह राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुल 1734 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, परंतु मात्र 500 करोड़ रुपये ही जारी किए गए। "यह सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है," वसावा ने कहा।

तीन साल पहले जब चैतर वसावा पहली बार डेडियापाड़ा से विधायक बने थे, तब उनका प्रभाव केवल नर्मदा जिले तक सीमित माना जाता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वे दक्षिण गुजरात से लेकर दाहोद तक की आदिवासी बेल्ट में आम आदमी पार्टी का चेहरा बन गए हैं। उनकी जनसभाओं में उमड़ने वाली भीड़ और आदिवासी युवाओं में दिखता उत्साह इस बात का संकेत है कि वसावा अब एक आंदोलनकारी नेता के रूप में देखे जा रहे हैं।

चैतर वसावा की उम्र मात्र 37 वर्ष है। वे 34 की उम्र में विधायक बने थे। उनका पहनावा, बोली और जीवनशैली आदिवासी समाज की परंपराओं से गहराई से जुड़ी है। वे गांवों में धरातलीय संपर्क रखते हैं और अपनी सादगी तथा संघर्षशील छवि के कारण जनता के बीच लोकप्रिय हो चुके हैं। आदिवासी रीति-रिवाजों के अनुसार उनकी दो पत्नियाँ हैं, और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही वसावा की राजनीतिक गतिविधियों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि चैतर वसावा धीरे-धीरे गुजरात की आदिवासी राजनीति का 'केजरीवाल मॉडल' बनते जा रहे हैं — जहां जनसंपर्क, आक्रोश और वैकल्पिक राजनीति की रणनीति भाजपा के परंपरागत वोट बैंक में सेंध लगा रही है।

भाजपा के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि गुजरात की कुल 27 आदिवासी सीटों में से अधिकांश पर उसका दबदबा रहा है। लेकिन वसावा की बढ़ती लोकप्रियता और 'गुजरात जोड़ो' अभियान के जरिए आम आदमी पार्टी की सक्रियता ने सत्तारूढ़ दल के भीतर हलचल मचा दी है।

गुजरात की राजनीति में अब चैतर वसावा का नाम केवल एक विधायक का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे जननेता के रूप में उभर रहा है, जो जेल से निकलकर जनजंगल के बीच नई राजनीतिक धारा बहा रहे हैं — और जिसका असर आने वाले चुनावों में भाजपा के समीकरणों को झकझोर सकता है।

राजस्थान के सिरोही में गुजरात के सैलानियों का 'फिल्मी फरार' 10,900 का खाना खाया, बोले "वॉशरूम जा रहे हैं" और गाड़ी में बैठकर भाग निकले, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

(जीएनएस)। सिरोही। राजस्थान के सिरोही ज़िले से एक अजीबोगरीब लेकिन चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है कि क्या आज की दिखावेभरी जिंदगी में ईमानदारी कहीं पीछे छूट चुकी है। मामला सियावा गांव के पास बने एक होटल 'हैपी डे' का है, जहां गुजरात से आए पांच सैलानियों ने 10,900 का खाना खाया और बिल चुकाए बिना फरार हो गए।

घटना 25 अक्टूबर की है। होटल स्टाफ के मुताबिक, शाम के समय एक कार में सवार चार पुरुष और एक महिला होटल पहुंचे। सभी ने आराम से खाना खाया, डेजर्ट तक का ऑर्डर दिया, और जब बिल लाया गया तो उन्होंने बड़े इत्मिनान से कहा – "ज़रा वॉशरूम जा रहे हैं।" इसके बाद वे सीधा होटल के बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में बैठे और तेज़ी से वहां से निकल गए।

होटल के सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में साफ़ दिखता है कि गुजरात नंबर की एक लक्ज़री गाड़ी

होटल से फुल स्पीड में निकलती है। जैसे ही होटल स्टाफ को शक हुआ कि सैलानी वापस नहीं आने वाले, उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खुद भी गाड़ी लेकर पीछे निकल पड़े।

होटल मालिक के मुताबिक, "बिल 10,900 का बना था। हम लोगों ने सोचा, ये लोग वॉशरूम गए हैं, लेकिन पांच मिनट बाद जब कार गायब दिखी तो सब समझ आ गया। हमने तुरंत पुलिस को बताया और पीछा किया।"

पुलिस और होटल कर्मियों ने मिलकर कुछ ही किलोमीटर आगे गुजरात बॉर्डर के पास इन लोगों को रोक लिया। इसी दौरान किसी ने मोबाइल फोन से पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड कर लिया। वायरल वीडियो में होटल का एक कर्मचारी गुस्से में सैलानियों से पूछता है —

"इतनी महंगी गाड़ियां रखते हो, लेकिन ईमानदारी का नाम नहीं जानते? 10,000 का खाना खाकर भाग गए?"

सैलानियों को रोकने के बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को बिल दिखाया और उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सैलानियों से पूछताछ की जा रही है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कई यूज़र्स ने सैलानियों की हरकत को 'घटिया मानसिकता' बताया। एक यूज़र ने लिखा, "भारत की यही समस्या है — गाड़ी EMI पर और ईमानदारी उधार पर। ये लोग बिल से नहीं, ज़िम्मेदारी से भागते हैं।"

एक अन्य ने तंज कसा, "10,900 का खाना खाया, लेकिन नैतिकता का स्वाद शायद भूल गए।"

वहीं, कई लोगों ने होटल स्टाफ और पुलिस की तत्परता की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह घटना सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि समाज में फैल रही दिखावे की प्रवृत्ति का आईना है — जहां लोग अपनी लक्ज़री लाइफ़स्टाइल दिखाने के लिए तो लाखों खर्च करते हैं, लेकिन ज़िम्मेदारी और सत्यनिष्ठा पर शून्य निवेश करते हैं।

इस घटना ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है — "क्या दिखावे की इस दौड़ में ईमानदारी कहीं खोती जा रही है?" लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामलों में केवल पुलिस नहीं, बल्कि समाज को भी संवेदनशील होने की ज़रूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति 'स्टेटस' दिखाने की चाह में बुनियादी इंसानियत को न भूले।

सिरोही की इस घटना ने यह साफ़ कर दिया है कि कभी-कभी वास्तविक अपराध केवल पैसों का नहीं, बल्कि चरित्र का दिवालियापन होता है — और यही सबसे बड़ी कीमत है जो आज की 'लक्ज़री' पीढ़ी चुका रही है।

खुले टैंक ने ली मासूम की जान: गाजियाबाद में नौ साल के प्रिंस की मौत ने खोली सरकारी लापरवाही की पोल

(जीएनएस)। गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में सरकारी लापरवाही ने एक और मासूम की जिंदगी लील ली। बिचपटा कॉलोनी में नगर पालिका परिषद द्वारा बनाए जा रहे सार्वजनिक शौचालय के खुले पड़े सेप्टिक टैंक में गिरकर नौ साल के बच्चे की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। यह टैंक पिछले तीन साल से खुला पड़ा था, शिकायतें कई बार हुईं, पर जिम्मेदार अफसरों ने कभी सुध नहीं ली। अब जब एक बच्चे की जान चली गई, तब प्रशासन हरकत में आया है।

बिचपटा कॉलोनी में सोनू नामक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका बेटा प्रिंस चौथी कक्षा में पढ़ता था। सोमवार की शाम प्रिंस अपने दोस्तों के साथ घर के बाहर खेल रहा था। खेलते-खेलते वह थोड़ी दूरी पर बने निर्माणाधीन शौचालय के पास पहुंच गया। वहीं पर खुला पड़ा सेप्टिक टैंक उसकी जान का जाल बन गया। कुछ देर बाद जब बच्चे घर नहीं लौटे, तो परिवार को चिंता हुई। आसपास के लोगों ने देखा कि टैंक का ढक्कन खुला

पड़ा है, और अंदर पानी भरा हुआ है। शक होने पर मजदूर बुलाए गए और टैंक से पानी निकलवाया गया। जब पानी कम हुआ तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं — भीतर प्रिंस का निश्चल शरीर डूबा पड़ा था। मजदूरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकाला और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह खबर फैलते ही पूरे इलाके में मातम छा गया। देखते-देखते सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई। लोगों में भारी आक्रोश था। उन्होंने नगर पालिका परिषद पर खुला आरोप लगाया कि उनकी लापरवाही और भ्रष्टाचार ने एक मासूम की जान ले ली। भीड़ ने ठेकेदार और नगर पालिका के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया।

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अंकित कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया और आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पीड़ित परिवार ने ठेकेदार और अधिकारियों के खिलाफ औपचारिक तहरीर थाने में दी है। पूर्व सभासद रोहतास जाटव और सभासद पति योगेंद्र जाटव ने भी प्रशासन को घेरते हुए कहा कि "यह दुर्घटना नहीं, हत्या है — नगर पालिका और ठेकेदार ने मिलकर बच्चे की जान ली है।" उन्होंने जिलाधिकारी से अपील की कि इस मामले में न केवल ठेकेदार बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सेप्टिक टैंक की शिकायतें पिछले तीन वर्षों से होती आ रही थीं। कई बार पत्राचार और मौखिक निवेदन किए गए, लेकिन न तो टैंक को ढंका गया, न ही चेतावनी का बोर्ड लगाया गया। नगर पालिका के अधिकारियों की उदासीनता अब एक मासूम की मौत का कारण बन गई।

भावनगर रेलवे मंडल के कर्मचारियों ने यात्री का भूलवश छूटा लैपटॉप सुरक्षित लौटाया

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के कर्मचारी अपने सम्मानित यात्रियों की सहायता हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। इसी प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण वेरावल स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ एक यात्री का लैपटॉप वाला बैग भूलवश छूट गया था, जिसे रेलवे कर्मचारियों ने अत्यंत ईमानदारी एवं जिम्मेदारी के साथ सुरक्षित रखकर यात्री को लौटा दिया।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि लगभग एक सप्ताह पूर्व वेरावल स्टेशन पर एक लावारिश बैग एक रेलवे कर्मचारी को मिला था। कर्मचारी द्वारा सतर्कता दिखाते हुए बैग को स्टेशन अधीक्षक कार्यालय में जमा कराया गया। जांच के दौरान बैग में एक लैपटॉप मिला। बैग की गहन जांच करने पर एक संपर्क नंबर प्राप्त हुआ, जिस पर संपर्क करने पर यात्री ने अपनी भूल स्वीकार की और रेलवे प्रशासन को धन्यवाद दिया। यात्री, जो राजस्थान के निवासी हैं, ने वापसी पर बैग प्राप्त करने का अनुरोध किया तथा रेलवे से उसे सुरक्षित रखने का आग्रह किया। यात्री की सुविधा को ध्यान में

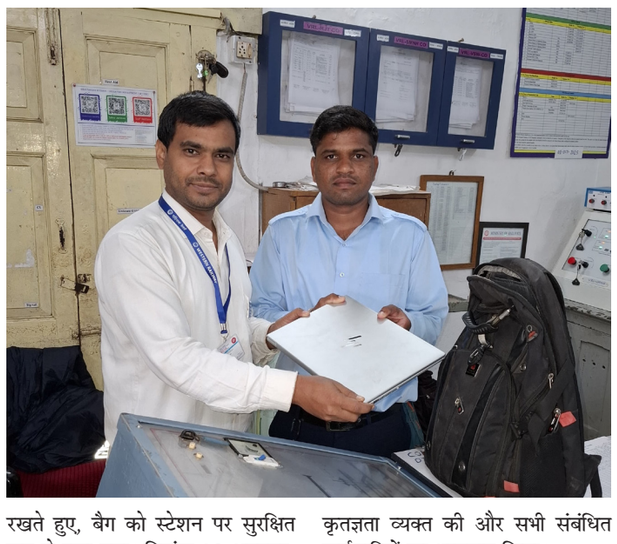

रखते हुए, बैग को स्टेशन पर सुरक्षित रूप से रखा गया। दिनांक 28 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) को संबंधित यात्री के वेरावल स्टेशन पर आगमन के पश्चात आवश्यक सत्यापन और पूछताछ के बाद लैपटॉप युक्त बैग उन्हें लौटा दिया गया। लैपटॉप सुरक्षित रूप से प्राप्त होने पर यात्री ने रेलवे प्रशासन के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की और सभी संबंधित कर्मचारियों का धन्यवाद किया।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए संबंधित कर्मचारियों की प्रशंसा करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि यह कार्य भारतीय रेल की ईमानदारी, जिम्मेदारी एवं यात्री सेवा की भावना का प्रतीक है।

मानसिक रोगियों की गरिमा पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: "जंजीरों में बांधना असंवैधानिक", निगरानी की जिम्मेदारी NHRC को सौंपी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी व्यवस्था और उसके मानवीय पक्ष को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है। अदालत ने साफ कहा है कि मानसिक रोगियों को जंजीरों में बांधना न सिर्फ क्रूर और अमानवीय है, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 — यानी गरिमा के साथ जीवन के मौलिक अधिकार — का खुला उल्लंघन है। अदालत ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले की पूरी निगरानी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को सौंप दी है। अब आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि देशभर में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 का सही ढंग से पालन हो और मानसिक रोगियों के साथ किसी भी प्रकार का अमानवीय व्यवहार न किया जाए।

यह जनहित याचिका अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल ने 2018 में दायर की थी। याचिका में दावा

किया गया था कि देश के कई राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के अहम प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा, जिससे मरीजों के मानवाधिकारों का लगातार हनन हो रहा है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के एक धार्मिक आश्रम में मानसिक रोगियों को जंजीरों से बांधे जाने की घटना का हवाला देते हुए कहा गया था कि इस तरह का व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम को जमीनी स्तर पर कैसे लागू किया जा रहा है। केंद्र की ओर से दायर हलफनामे में बताया गया कि देशभर में केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (CMHA), राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण (SMHA) और मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड (MHRB) का गठन हो चुका है। अदालत ने इन संस्थाओं के कामकाज की निगरानी और मूल्यांकन का कार्य NHRC को सौंपते हुए कहा कि आयोग समय-समय पर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे और यह सुनिश्चित करे कि मरीजों के अधिकारों की रक्षा हो।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मानसिक बीमारी किसी अपराध की तरह नहीं देखी जा सकती। इस स्थिति में जी रहे व्यक्ति को सहानुभूति, चिकित्सा और सम्मान की आवश्यकता होती है, न कि बेड़ियों और अपमान की। अदालत ने राज्यों को भी निर्देश दिया कि वे अपने-अपने इलाकों में निजी और सरकारी मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों की स्थिति की समीक्षा करें, यह सुनिश्चित करें कि वहां किसी भी मरीज को बंदी बनाकर या हिंसक तरीके से नहीं रखा जा रहा है।

2017 में बने मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम का मकसद मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को एक अधिकार-आधारित प्रणाली में शामिल करना था, ताकि किसी व्यक्ति की बीमारी उसकी गरिमा और स्वतंत्रता को छीन न सके। इस अधिनियम के तहत मरीज को इलाज का अधिकार, अपनी सहमति से उपचार का विकल्प चुनने का अधिकार और संस्थागत देखभाल में मानवीय व्यवहार का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम ने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज और शासन दोनों के लिए एक गहरी चेतावनी दी है। अदालत का यह आदेश न सिर्फ मानसिक रोगियों की पीड़ा की ओर ध्यान दिलाता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि सभ्यता की कसौटी इस बात से तय होती है कि हम अपने सबसे कमजोर नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अब NHRC पर यह नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह इस आदेश को सिर्फ दस्तावेज़ों में नहीं, बल्कि जमीन पर लागू होते हुए देखे।

परिमल नाथवाणी ने तोड़ी चुप्पी: "गिर लायन सफारी में सभी अनुमति ली थी, मैं शेरों से प्रेम करता हूं, उनके संरक्षण के लिए जीवन समर्पित है"

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान में लायन सफारी के दौरान उद्योगपति मुकेश अंबानी के करीबी और राज्यसभा सांसद परिमल नाथवाणी का शेरों के बीच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। वीडियो में नाथवाणी अपनी निजी कार से सफारी करते हुए और शेरों के बेहद करीब जाकर उनका वीडियो बनाते दिखाई दिए। जैसे ही यह वीडियो इंटरनेट पर आया, लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या आम लोगों के लिए लागू वन नियम और कानून बड़े लोगों के लिए अलग हैं। कई यूज़र्स ने वन विभाग और गुजरात सरकार से यह भी पूछा कि क्या नाथवाणी को इस तरह की सफारी के लिए कोई विशेष अनुमति दी गई थी।

विवाद बढ़ने के बाद परिमल नाथवाणी ने खुद सोशल मीडिया पर एक लंबा बयान जारी कर अपनी चुप्पी तोड़ी और पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने लिखा, "मैं पिछले तीन दशकों से नियमित रूप से गिर का दौरा करता रहा हूं। हर बार

मैंने गुजरात सरकार के वन विभाग से आवश्यक अनुमतियाँ और स्वीकृतियाँ प्राप्त की हैं। मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरी उपस्थिति से जंगल के प्राकृतिक वातावरण या शेरों के जीवन में कोई व्यवधान न आए। जंगल में प्रवेश के लिए चाहे निजी वाहन हों या मेरे साथ आने वाले लोग, सभी के लिए अनुमतियाँ वन विभाग से ली जाती हैं।"

नाथवाणी ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया कि उनका शेरों से संबंध केवल पर्यटक या उद्योगपति के तौर पर नहीं, बल्कि एक वन्यजीव प्रेमी और संरक्षणकर्ता के रूप में है। उन्होंने लिखा, "मैं एक वन्यजीव प्रेमी हूं। गिर के शेरों से मेरा गहरा आत्मिक लगाव है। मैंने शेर संरक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से काम किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के माध्यम से भी हमने शेरों और उनके आवास क्षेत्र की सुरक्षा के लिए कई पहलें की हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि गिर केवल गुजरात का नहीं, बल्कि पूरे भारत का गौरव है।"

नाथवाणी ने बताया कि उन्होंने शेर संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अनेक रचनात्मक प्रयास भी किए हैं। उन्होंने दो प्रसिद्ध पुस्तकें 'गिर लायनः प्राइड ऑफ गुजरात' और 'कॉल ऑफ द गिर' लिखी हैं, जिनमें उन्होंने एशियाई शेरों के इतिहास, पारिस्थितिकी और संरक्षण प्रयासों का विस्तृत विवरण दिया है। इसके अलावा उन्होंने 'द प्राइड किंगडम' नामक एक वृत्तचित्र फिल्म का भी निर्माण किया है, जिसमें गिर के शेरों के जीवन, उनकी पारिवारिक संरचना और जंगल की पारिस्थितिकीय जटिलताओं को सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है।

नाथवाणी ने गिर के मशहूर शेरों की जोड़ी "जय-वीरू" का भी उल्लेख करते हुए कहा, "इन दोनों शेरों का जीवन गिर की आत्मा का प्रतीक था। मैंने उनकी स्मृति में भी एक विशेष डॉक्युमेंट्री बनाई है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जान सकें कि इन शेरों ने गिर की जैव विविधता को कितना समृद्ध किया।"

वायरल वीडियो पर आई प्रतिक्रियाओं को लेकर नाथवाणी ने संयमित प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मैं उन सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं जिन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त की है। मैं इस संवाद को सकारात्मक रूप में देखता हूं क्योंकि यह दर्शाता है कि लोग वन्यजीव संरक्षण के प्रति सचेत हैं। गिर और उसके शेर हमारे गर्व का प्रतीक हैं और मैं जीवनभर उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए समर्पित रहूंगा।"

परिमल नाथवाणी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में डायरेक्टर (कॉरपोरेट अफेयर्स) हैं और आंध्र प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं, लंबे समय से गिर क्षेत्र और एशियाई शेरों से जुड़ी परियोजनाओं में सक्रिय हैं। उन्होंने कई बार संसद में भी शेर संरक्षण और गिर वन की स्थिति पर प्रश्न उठाए हैं।

हालांकि, सोशल मीडिया पर उठे इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में वन्यजीव पर्यटन और संरक्षण के नियम सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं। नाथवाणी के विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद अब यह मामला कुछ हद तक शांत होता नजर आ रहा है, लेकिन गिर के शेरों और उनके संरक्षक के रूप में उनका नाम एक बार फिर राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है।

कटनी में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या से मचा कोहराम, आरोपी के पिता ने फांसी लगाकर दी जान, थाना प्रभारी लाइन हाजिर

(जीएनएस)। कटनी। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में मंगलवार को हुई एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व पदाधिकारी नीलेश रजक की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात कैमोर नगर के बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुई, जहां बाइक पर सवार नकाबपोश हमलावरों ने गोली चलाकर नेता की जान ले ली। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है। हत्या के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए सड़क पर उतरकर हंगामा कर दिया।

घटना मंगलवार सुबह करीब 11 बजे की है। नीलेश रजक बाइक से बाजार जा रहे थे, तभी अचानक पीछे से आई एक काली बाइक पर सवार दो नकाबपोश युवकों ने उन्हें रोक लिया। इससे पहले कि नीलेश कुछ समझ पाते, हमलावरों ने सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही नीलेश वहीं सड़क पर गिर पड़े और खून से लथपथ हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने आनन-फानन में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हत्या की खबर पूरे क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते कैमोर नगर की गलियां पुलिस सायरनों और नारों से गूंज उठीं।

घटना के कुछ ही घंटों बाद एक और चौंकाने वाली खबर आई। हत्याकांड में नामजद आरोपी प्रिंस जोसेफ के पिता नेल्सन जोसेफ ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया गया कि उन्होंने घर लौटने के बाद परिवार के साथ सामान्य बातचीत की और फिर कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। जब देर तक वे बाहर नहीं निकले, तो परिजनों ने झांका और देखा कि वे पंखे से लटके हुए थे। इससे पूरे मोहल्ले में सन्नाटा फैल गया। बताया जा रहा है कि बेटे के हत्याकांड में नाम आने और पुलिस दबाव की वजह से वे मानसिक तनाव में थे।

इस हत्याकांड ने पूरे प्रशासन को हिला दिया। कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने तत्काल एक्शन लेते हुए कैमोर थाना प्रभारी अरविंद चौबे और प्रधान आरक्षक प्रेमशंकर पटेल को लाइन हाजिर कर दिया। वहीं, जबलपुर डीआईजी अतुल सिंह खुद कैमोर पहुंचे और फ्लैग मार्च निकालकर स्थिति का जायजा लिया। इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

हत्या से गुस्साए परिजनों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शव का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने विजयराघवगढ़ अस्पताल के सामने छह घंटे तक चक्काजाम कर दिया। मौके पर विधायक संजय पाठक और अन्य भाजपा नेता पहुंचे और परिजनों को समझाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से बात कर घटना पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं और दोषियों को हर हाल में सख्त सजा मिलनी चाहिए। उधर, स्थानीय लोगों में यह चर्चा है कि नीलेश रजक का नाम हाल ही में कुछ विवादित मामलों में आया था, जिसकी वजह से उनके दुश्मनों की संख्या बढ़ गई थी। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

कटनी का यह मामला राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों मोर्चों पर गरमाया हुआ है। एक ओर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, वहीं आरोपी के पिता की आत्महत्या ने इस मामले को और भी जटिल बना दिया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा।

बिहार के दरभंगा से गुजरात सचिवालय तक — कौन हैं एम. के. दास, जो संभालेंगे राज्य की नौकरशाही की सबसे बड़ी कमान

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने 1990 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार दास (एम. के. दास) को गुजरात का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वे 1 नवंबर से यह पदभार संभालेंगे। मौजूदा मुख्य सचिव पंकज जोशी 31 अक्तूबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और उनके बाद एम. के. दास राज्य की नौकरशाही की कमान संभालेंगे।

एम. के. दास वर्तमान में गृह विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर कार्यरत हैं और गुजरात के भीतर प्रशासनिक रणनीति, उद्योग और नीति निर्माण में उनकी गहरी पकड़ मानी जाती है। दास के चयन को राज्य सरकार का एक "संतुलित और अनुभवी प्रशासन" की ओर संकेत माना जा रहा है।

मनोज कुमार दास का जन्म 20 दिसंबर 1966 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पले-बढ़े दास शुरू से ही मेधावी छात्र रहे। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से बी.टेक (ऑनर्स) की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा दी और 1990 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) में चयनित हुए। उन्होंने गुजरात कैडर चुना, जो उनके करियर का स्थायी

ठिकाना बना।

उनकी पहली नियुक्ति वडोदरा में बतौर जिला विकास अधिकारी (डीडीओ) के रूप में हुई। इसके बाद दास ने राज्य के लगभग हर अहम प्रशासनिक मोर्चे पर काम किया — चाहे वह सूरत और वडोदरा नगर निगमों के आयुक्त के रूप में हो या गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (GSPC) के प्रबंध निदेशक के तौर पर। उनके कार्यकाल में कई औद्योगिक परियोजनाओं ने गति पकड़ी और राज्य के निवेश वातावरण को मजबूती मिली।

एम. के. दास ने उद्योग एवं खनन विभाग (Industries and Mines Department) में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य किया, जहां उन्होंने राज्य की औद्योगिक नीतियों को नई दिशा दी। उनके काम का सबसे बड़ा पहलू यह माना जाता है कि वे टीम वर्क और व्यवहारिक नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं।

उनकी पत्नी अनुराधा दास एक जानी-मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो महिला शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में सक्रिय हैं।

एम. के. दास का कार्यकाल लगभग 14 महीने का रहेगा, क्योंकि वे 20 दिसंबर 2026 को सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, राज्य सरकार चाहे तो उन्हें आगे विस्तार भी दे सकती है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब राज्य सरकार को किसानों के मुद्दों, शहरी चुनावों और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

दास की खासियत यह है कि वे शांत, मिलनसार और संतुलित स्वभाव वाले अधिकारी माने जाते हैं। अधिकारियों और मंत्रियों के बीच उनकी छवि एक ऐसे प्रशासक की है जो संवाद और सहयोग के जरिये निर्णय लेना पसंद करते हैं। गृह सचिव के रूप में दास की डिप्टी सीएम हर्ष संघवी के साथ अच्छी समझ और समन्वय पहले से स्थापित है। अब मुख्य सचिव बनने के बाद यह तालमेल राज्य सरकार के प्रशासनिक निर्णयों को और मजबूत बना सकता है।

गुजरात के राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि दास की नियुक्ति मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की टीम में एक नया संतुलन लाएगी — खासकर तब जब राज्य अगले दो वर्षों में महानगर पालिका और विधानसभा चुनावों की दिशा में बढ़ रहा है।

दरभंगा के एक साधारण विद्यार्थी से लेकर गुजरात सरकार के सर्वोच्च नौकरशाह बनने तक एम. के. दास की यात्रा यह साबित करती है कि प्रशासनिक कुशलता, शांति और ईमानदारी अब भी भारतीय नौकरशाही में सफलता की सबसे बड़ी पहचान हैं।

आरा की जनता का इम्तिहान: 37 हज़ार की संपत्ति वाले अंसारी बनाम करोड़पति राजनीति

(जीएनएस)। आरा। बिहार की राजनीतिक फिज़ा में इस बार कुछ अलग गूंज सुनाई दे रही है। जहां ज्यादातर उम्मीदवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, वहीं आरा विधानसभा सीट से भाकपा (माले) लिबरेशन के उम्मीदवार कय्यूमुद्दीन अंसारी अपनी मात्र 37 हज़ार रुपये की संपत्ति के साथ मैदान में हैं। लेकिन यह रकम उनकी ताकत नहीं, बल्कि जनता का उन पर भरोसा ही उनका सबसे बड़ा पूंजी है। आरा विधानसभा सीट, जो फिलहाल भाजपा के कब्जे में है, पर इस बार मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है। भाजपा ने संजय सिंह 'टाइगर' को टिकट दिया है, जबकि अंसारी का दावा है कि "पैसे की राजनीति को जनता की ताकत हराएगी।" वे याद दिलाते हैं कि 2020 के चुनाव में वे सिर्फ तीन हजार वोट से पीछे रह गए थे। "मैं हारा हुआ नहीं, जीतता हुआ उम्मीदवार हूं," अंसारी आत्मविश्वास से कहते हैं। अंसारी का चुनाव अभियान अनोखा है—न कोई बड़े पोस्टर, न मोटरकेड, न महंगे मंच। उनके प्रचार की गाड़ी जनता के भरोसे चलती है। गांव-गांव में सभाओं के दौरान लोग खुद चंदा देते हैं, खाना खिलाते हैं, और उनके लिए नारे लगाते हैं। "हमारे पास पैसे नहीं, लेकिन जनता का प्यार है। यह प्यार किसी करोड़पति के खाते में नहीं मिलेगा," वे मुस्कुराते हुए कहते हैं।

50 वर्षीय अंसारी पसमांदा मुस्लिम समुदाय से आते हैं। उनके पिता के पास कोई जमीन नहीं थी। वह खुद पार्टी के पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं और उनकी पत्नी आंगनबाड़ी में काम करती हैं। "हमने गरीबी देखी है, लेकिन कभी अपनी जड़ें नहीं छोड़ीं," वे बताते हैं।

अंसारी अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहते हैं, "जो हमारे सामने हैं, वे वोट चोरी की राजनीति करते हैं। हम जनता की राजनीति करते हैं, जहां लोग 10-20 रुपये देकर भी लोकतंत्र को मजबूत करते हैं।"

यह अंसारी का तीसरा चुनाव है। 2015 में उन्हें पांच हजार वोट मिले थे और 2020 में वे जीत के बेहद करीब पहुंच गए। इस बार उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता बदलाव के मूड में है। "अब आरा के लोग नौकरी चोरों, वोट चोरों और खजाना चोरों को जवाब देने वाले हैं," वे कहते हैं।

उन पर हत्या के प्रयास और दंगा भड़काने जैसे नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन अंसारी इन मामलों को "जन आंदोलनों की कीमत" बताते हैं। "जब आप गरीबों और मजदूरों के हक़ की लड़ाई लड़ते हैं, तो सत्ता आपको अपराधी बना देती है," उनका कहना है।

शाहाबाद क्षेत्र की कुल 22 सीटों में पिछली बार राजग को सिर्फ आरा और बड़हरा से जीत मिली थी। लेकिन इस बार चुनावी माहौल शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर गर्म है। अंसारी का कहना है, "नीतीश कुमार के 20 साल के शासन में एक पूरी पीढ़ी बेरोजगार हो गई। जो बच्चा नीतीश जी के सत्ता में आने पर पैदा हुआ था, वो आज नौकरी की तलाश में है। यह सरकार फेल हो चुकी है।"

वे याद दिलाते हैं कि "जब हम 17 महीनों के लिए सत्ता में थे, तो पांच लाख युवाओं को रोजगार दिया। हमने 10 लाख नौकरियों का वादा किया तो नीतीश जी ने मजाक उड़ाया, लेकिन बाद में खुद 19 लाख की बात करने लगे।"

अंसारी ने भाजपा और नीतीश सरकार पर भी हमला बोला—"बुलडोजर राज, पेपर लीक और बेरोजगारी, यही उनका मॉडल बन गया है। जनता अब बदलाव के लिए तैयार है, और इस बार का युवा जनादेश तय करेगा कि बिहार किस दिशा में जाएगा।"

अमेरिका बॉर्डर पर भारतीयों की हिरासत में 62% गिरावट, चार साल में सबसे कम आंकड़ा — 'डंकी रूट' से घटा उत्साह, बढ़ा डर और सतर्कता

(जीएनएस)। अहमदाबाद। अवैध रूप से अमेरिका पहुंचने की कोशिश करने वाले भारतीयों की संख्या में इस साल भारी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा बल (CBP) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच 34,146 भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष में यह संख्या 90,415 थी — यानी लगभग 62 प्रतिशत की कमी। यह पिछले चार वर्षों में अमेरिकी सीमा पर पकड़े गए भारतीयों की सबसे कम संख्या है।

अमेरिकी एजेंसी द्वारा 28 अक्टूबर को जारी रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सितंबर 2024 में केवल 1,147 भारतीयों को पकड़ा गया, जबकि 2022 में यह संख्या 63,927 थी — यानी लगभग 47 प्रतिशत की गिरावट। आंकड़ों से स्पष्ट है कि भारतीयों की हिस्सेदारी अब कुल सीमा पार गिरफ्तारियों में पहले की तुलना में काफी कम हो गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2024 में अमेरिकी सीमाओं पर कुल 2.9 मिलियन

(29 लाख) मुठभेड़ें दर्ज की गईं, जो 2023 के 3.2 मिलियन से कम हैं। हालांकि 2022 की तुलना में यह संख्या थोड़ा अधिक है। इस अवधि में पकड़े गए भारतीयों में से 31,480 अकेले युवा पुरुष थे, जबकि 2,552 परिवारों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा, 91 नाबालिग बिना किसी अभिभावक के पकड़े गए और 23 बच्चे वयस्कों के साथ पाए गए।

इन आंकड़ों के पीछे सबसे बड़ा कारण है तथाकथित 'डंकी रूट' (Donkey Route) — यानी वह गुप्त, खतरनाक और गैरकानूनी रास्ता जिसके जरिए भारतीय एजेंट अमेरिका पहुँचाने का दावा करते हैं। गुजरात के उत्तरी और मध्य इलाकों में यह नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय रहा है। लेकिन 2022 में अमेरिका–कनाडा बॉर्डर के पास डिंगुचा गांव के एक परिवार की ठंड से मौत और 2023 में रियो ग्रांडे नदी में एक अन्य भारतीय परिवार की डूबकर मौत की घटनाओं के बाद यह नेटवर्क लगभग ठहर गया।

इन दर्दनाक हादसों के बाद न केवल भारतीय परिवारों में भय बढ़ा बल्कि अमेरिकी और भारतीय एजेंसियों ने भी तस्करी मार्गों पर शिकंजा कस दिया। कई स्थानीय एजेंटों पर कार्रवाई हुई और कई गिरोह भंग कर दिए गए। इसके परिणामस्वरूप अब लोग ऐसे खतरनाक रास्तों पर जाने से पहले दस बार सोचने लगे हैं।

एक वरिष्ठ आव्रजन अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "अमेरिका जाने का रास्ता अब एक 'लाइफ–चेंजिंग जुआ' बन गया है। संख्या में कमी का मतलब यह नहीं है कि वहां जाने की इच्छा खत्म हो गई है, बल्कि अब जोखिम पहले से कहीं ज़्यादा स्पष्ट और महंगे हो गए हैं।" विशेषज्ञों का मानना है कि यह गिरावट कई कारकों का परिणाम है — जिनमें अमेरिकी सीमा पर सख्त प्रवर्तन, भारत में जोखिमों को लेकर बढ़ती जागरूकता, और तस्करी नेटवर्क की बदलती रणनीतियाँ शामिल हैं। गुजरात, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में हाल के वर्षों में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने ऐसे एजेंटों पर कड़ा शिकंजा कसा है। हालांकि, प्रवासन शोधकर्ताओं का कहना है कि भारत में रोजगार के अवसरों में ठहराव, उच्च शिक्षा की चाह और डॉलर में आमदनी के सपने अब भी युवाओं को आकर्षित करते हैं। लेकिन 2022 और 2023 की त्रासदियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डंकी रूट पर जाने का मतलब अब "एक जोखिमभरा जुआ" है — जिसमें जान और भविष्य दोनों दांव पर लग जाते हैं।

अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, सीमाओं पर पकड़े गए नाबालिग बच्चों की उपस्थिति एक गंभीर मानवीय चिंता का विषय बनी हुई है। कई तस्करी नेटवर्क अब भी इस चाल में लगे हैं कि बच्चों को आगे भेजकर अमेरिकी एजेंसियों से नरमी हासिल की जा सके। लेकिन अब इस पर भी नकेल कस दी गई है।

कुल मिलाकर, अमेरिका की सीमा पर भारतीयों की घटती गिरफ्तारी यह संकेत देती है कि अब 'डंकी रूट' का खौफ हकीकत बन चुका है — जहां कभी अमेरिकी सपनों का लालच था, वहां अब मौत और जोखिम की यादें हैं। और शायद यही कारण है कि इस साल पहली बार, भारतीय प्रवासन की यह 'अंधेरी सड़क' इतनी शांत दिखाई दे रही है।

ड्रिंक एंड ड्राइव पर अब 'कवच' से लगेगी लगाम — वडोदरा के इनोवेटर मिथिलेश पटेल ने बनाई ऐसी डिवाइस जो गाड़ी ही नहीं चलने देगी

(जीएनएस)। अहमदाबाद। शराब पीकर गाड़ी चलाना देशभर में सड़क हादसों की बड़ी वजह बन चुका है। कानून सख्त हैं — पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 का जुर्माना या छह महीने की जेल, दूसरी बार 15,000 जुर्माना और दो साल की सजा — लेकिन हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब गुजरात के एक होनहार इनोवेटर मिथिलेश पटेल ने इस गंभीर समस्या का तकनीकी समाधान निकाल लिया है। उन्होंने एक अनोखी डिवाइस बनाई है — "कवच" (Kavach) — जो शराब पीकर ड्राइव करने वाले व्यक्ति को गाड़ी चलाने ही नहीं देगी।

मिथिलेश पटेल, जिन्हें गुजरात का 'सोनम वांगचुक' कहा जा रहा है, वडोदरा के रहने वाले हैं और अब तक 140 पेटेंट अपने नाम कर चुके हैं। इनमें से 101 पेटेंट उन्होंने ओपन सोर्स घोषित किए हैं ताकि युवा इनोवेटर, स्टार्टअप्स और शैक्षणिक संस्थान उनका उपयोग आगे के शोध के लिए कर सकें।

कैसे काम करती है "कवच" डिवाइस?

यह डिवाइस वाहन में इस तरह लगाई जाती है कि वह ड्राइवर और सह-यात्री दोनों की सांस में मौजूद अल्कोहल स्तर का तुरंत पता लगा सके। यदि सिस्टम को यह पता चलता है कि ड्राइवर ने निर्धारित सीमा से अधिक शराब पी रखी है, तो यह अपने आप वाहन का इग्निशन बंद कर देता है या फ्यूल सप्लाई रोक देता है। इतना ही नहीं, यह सिस्टम एक ईमेल अलर्ट भेजता है जिसमें उस व्यक्ति का अल्कोहल लेवल लिखा होता है।

यदि कोई व्यक्ति डिवाइस को

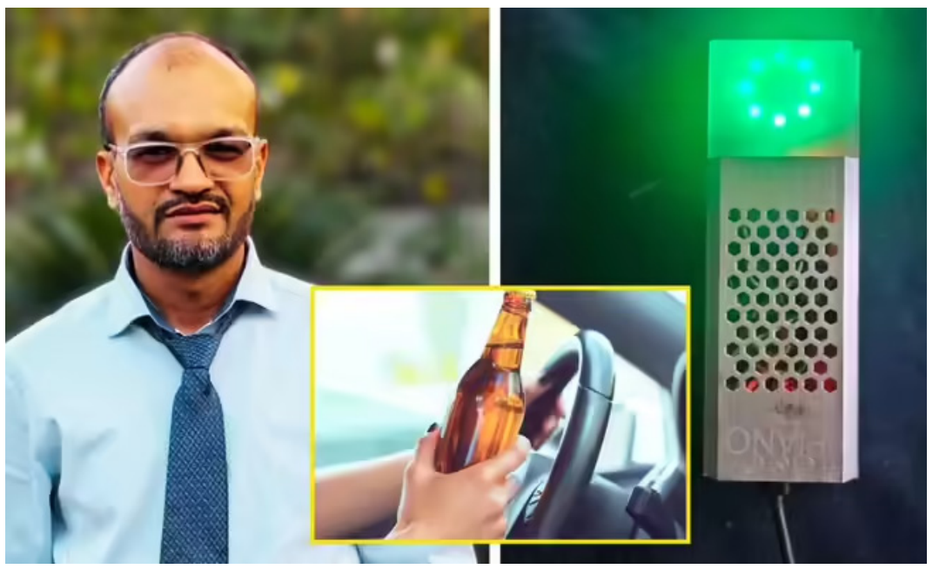

बाईपास करने की कोशिश करता है, तो "कवच" हर 15 सेकंड में ड्राइवर की सांस को स्कैन करता है। यदि दोबारा शराब का स्तर पाया जाता है, तो गाड़ी के विंडशील्ड के पास एक लाल चेतावनी लाइट जल उठती है जिसे पुलिस आसानी से देख सकती है। कम स्तर मिलने पर पीली लाइट चेतावनी देती है। इस तरह यह डिवाइस गाड़ी को चलने से पहले ही रोक देती है, जिससे नशे में ड्राइविंग की संभावना लगभग खत्म हो जाती है।

मिथिलेश पटेल ने बताया कि इस डिवाइस का उपयोग सिर्फ वाहनों में ही नहीं, बल्कि सरकारी दफ्तरों, फैक्टरियों और कॉर्पोरेट संस्थानों में भी किया जा सकता है, जहां नशे की हालत में प्रवेश वर्जित है। "कवच" को ड्रोन पर भी लगाया जा सकता है ताकि शराब भंडारण या अवैध बिक्री स्थलों की हवा से स्कैनिंग की जा सके।

गुजरात और बिहार जैसे राज्यों के लिए वरदान

पटेल का कहना है कि यह तकनीक उन राज्यों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है जहां शराबबंदी लागू है — जैसे गुजरात और बिहार। "कवच" हवा में मौजूद अल्कोहल के सूक्ष्म अंश तक को पहचान सकता है, जिससे यह अवैध शराब के उपयोग और बिक्री की निगरानी में भी सहायक होगा।

40 वर्षीय इनोवेटर की प्रेरक कहानी

वडोदरा के वासना रोड पर रहने वाले मिथिलेश पटेल ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था, लेकिन पढ़ाई बीच में छोड़ दी। बावजूद इसके, उन्होंने पिछले 22 वर्षों में 140 से अधिक पेटेंट हासिल किए। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" विजन से गहरा लगाव है। उनका सपना है कि भारत को इनोवेशन और रिसर्च के माध्यम से दुनिया का तकनीकी महाशक्ति बनाया जाए।

मिथिलेश पटेल कहते हैं — "शराब पीकर वाहन चलाने वाले न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं। अगर 'कवच' जैसी तकनीक हर वाहन में अनिवार्य कर दी जाए, तो हम हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं।" उनकी इस सोच और खोज ने गुजरात में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है — क्या अब तकनीक, इंसान की गैर-जिम्मेदारी को रोकने का सबसे असरदार 'कवच' बन सकती है?

दिल्ली से 31 गुना बड़ा है देश का सबसे विशाल जिला, जिससे छोटे हैं कई राज्य भी ,जानिए कच्छ की अद्भुत कहानी

(जीएनएस)। भारत का भूगोल जितना विविध है, उतना ही रोमांचक भी। उत्तर में हिमालय की चोटियां हैं, दक्षिण में समंदर की लहरें, पूर्व में चाय के बागान हैं तो पश्चिम में अनंत फैलाव लिए रेगिस्तान। इन्हीं भौगोलिक अद्भुतताओं के बीच भारत का एक ऐसा जिला भी है, जो अपनी विशालता के कारण न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है। यह जिला है गुजरात का कच्छ — भारत का सबसे बड़ा जिला, जो अपने विस्तार, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक विविधता के कारण देश की अनोखी पहचान रखता है।

कच्छ का क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है। यह आंकड़ा सुनने में भले ही एक सांख्यिकीय तथ्य लगे, लेकिन जब इसे तुलना में रखा जाए तो इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। यह जिला हरियाणा, केरल और गोवा जैसे राज्यों से बड़ा है। यहां तक कि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो कच्छ अकेला ही दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह — इन सभी के कुल क्षेत्रफल से भी कहीं अधिक फैला हुआ है। दिल्ली के मुकाबले तो यह 31 गुना बड़ा है और गोवा से 12 गुना से भी ज्यादा विशाल। गुजरात का लगभग 23 प्रतिशत भूभाग अकेले कच्छ जिले के हिस्से में आता है, यानी गुजरात का लगभग चौथाई हिस्सा इसी एक जिले में समाया हुआ है।

इतना बड़ा जिला होना जहां गर्व की बात

है, वहीं प्रशासनिक दृष्टि से यह एक बड़ी चुनौती भी है। 2011 की जनगणना के अनुसार कच्छ की कुल जनसंख्या लगभग 20 लाख 92 हजार थी। इस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बहुत कम है क्योंकि इसका अधिकांश भाग दलदली या रेगिस्तानी है। रण ऑफ कच्छ, जो मानसून में जलमग्न हो जाता है और सर्दियों में नमक की सफेद परत से ढक जाता है, इस जिले का सबसे बड़ा भू-भाग है। यही रण इस जिले को रहस्यमय और अद्भुत बनाता है। सर्दियों की धूप में जब यह रण चमकता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो धरती पर किसी ने रजत की चादर बिछा दी हो। यही दृश्य हर साल हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों को यहां खींच लाता है।

कच्छ केवल भौगोलिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां देश का सबसे ज्यादा नमक बनाया जाता है। नमक के विशाल मैदानों में मेहनतकश लोग साल भर मेहनत करते हैं और यह नमक पूरे देश में पहुंचता है। इसके अलावा यह इलाका अपने हस्तशिल्प और लोककला के लिए भी मशहूर है। कच्छ की कढ़ाई, आभूषण, लकड़ी का काम और हस्तनिर्मित वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। यहां की मिट्टी से बनी कलाकृतियां और कच्छ के लोगों की रंगीन पारंपरिक पोशाकें भारतीय संस्कृति की जीवंत मिसाल हैं।

इतने विशाल आकार और सीमित जनसंख्या के कारण कई बार कच्छ को विभाजित करके दो जिलों में बांटने की मांग उठती रही है। प्रशासनिक प्रबंधन की कठिनाइयों को देखते हुए सरकारें भी इस पर विचार करती रही हैं। लेकिन कच्छ के लोग अपनी एकता और पहचान को बनाए रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि कच्छ केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक आत्मा है, जिसे विभाजित करना इसकी पहचान को कमजोर करना होगा।

कच्छ आज औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी देश का प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहां स्थित मुंद्रा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख द्वार है। इसके अलावा कच्छ में विशाल पवन ऊर्जा फार्म और सोलर पार्क स्थापित किए गए हैं, जो इसे देश के नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र के रूप में अग्रणी बनाते हैं। यहां से न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश को हरित ऊर्जा की आपूर्ति होती है। इतिहास की दृष्टि से भी कच्छ का विशेष महत्व है। यहां स्थित धोलावीरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख अवशेष है। धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह प्रमाण है कि हजारों वर्ष पहले भी इस भूमि पर एक उन्नत और संगठित सभ्यता का विकास हुआ था। कच्छ में देश का एकमात्र जंगली गधा अभयारण्य भी है, जो यहां की जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को दर्शाता है। जहां कच्छ देश का सबसे बड़ा जिला है, वहीं पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश का माहे भारत का सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल केवल नौ वर्ग किलोमीटर है और यह पूरी तरह से केरल राज्य से घिरा हुआ है। यहां की आबादी लगभग 40 हजार है। पुदुचेरी का ही यानम जिला भी देश का दूसरा सबसे छोटा जिला है, जिसका क्षेत्रफल करीब 30 वर्ग किलोमीटर है।

भारत में क्षेत्रफल की यह विविधता केवल भौगोलिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक विरोधाभासों की भी झलक देती है। एक ओर कच्छ जैसा जिला है जो इतना विशाल है कि दिल्ली जैसे शहर उसके सामने छोटा पड़ता है, और दूसरी ओर माहे जैसा छोटा-सा क्षेत्र है जो अपने भीतर सादगी और सौहार्द का प्रतीक है।

जनसंख्या के आधार पर देखें तो भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। इसकी आबादी दो करोड़ से अधिक है, जो कई राज्यों की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। मुंबई की आबादी गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नगालैंड और मेघालय जैसे राज्यों की आबादी को पीछे छोड़ देती है।

कच्छ का नाम सुनते ही मन में सफेद रण, ऊंट, पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और सूर्यास्त का अद्भुत नजारा घूम जाता है। यह केवल एक जिला नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का वह टुकड़ा है जो आधुनिक विकास और प्राचीन परंपरा दोनों को साथ लेकर चलता है। कच्छ की मिट्टी, नमक और हवा में भारत की विविधता की सच्ची गंध बसती है — यही वजह है कि कच्छ न केवल गुजरात की शान है, बल्कि पूरे देश का गर्व है।

ब्लाउज सिलने में देर दर्जी को पड़ी भारी, महिला को मिलेगा मुआवजा ,अहमदाबाद उपभोक्ता कोर्ट का सख्त आदेश

(जीएनएस)। अहमदाबाद। कभी-कभी छोटी-सी लापरवाही भी बड़ी कानूनी सजा में बदल जाती है। गुजरात के अहमदाबाद में एक दर्जी को महिला का ब्लाउज समय पर तैयार न करने के कारण जुर्माना भरना पड़ेगा। मामला एक ऐसे विवाद का है जिसमें ग्राहक के अधिकार और सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी दोनों का अहम उदाहरण पेश हुआ है।

यह पूरा मामला 2024 का है जब नवरंगपुरा क्षेत्र की एक महिला ने अपने रिश्तेदार की शादी के लिए ब्लाउज सिलवाने का ऑर्डर दिया था। महिला ने अहमदाबाद की प्रसिद्ध सीजी रोड स्थित एक दर्जी की दुकान में ब्लाउज की सिलाई के लिए 4,395 रुपये अग्रिम भुगतान के रूप में दिए थे। दर्जी ने वादा किया था कि ब्लाउज शादी से पहले पूरी तरह तैयार हो जाएगा ताकि ग्राहक उसे समारोह में पहन सके। शादी की तारीख 24 दिसंबर तय थी।

लेकिन जब महिला 14 दिसंबर को ब्लाउज लेने पहुंची तो सामने आया कि ब्लाउज न तो तय माप में था और न ही उसकी बताई गई डिजाइन के अनुरूप। दर्जी ने उसे यह कहकर लौटाया कि वह ब्लाउज को ठीक करवाकर शादी से पहले दे देगा। मगर जैसे-जैसे तारीख नजदीक आई, सिलाई की डिलीवरी नहीं हुई। शादी बीत गई, लेकिन ब्लाउज नहीं मिला।

हताश होकर महिला ने दर्जी को कानूनी नोटिस भेजा और उपभोक्ता विवाद निवारण

आयोग में शिकायत दर्ज की। सुनवाई के दौरान दर्जी आयोग में पेश नहीं हुआ, जिससे मामला एकतरफा सुनवाई में बदल गया। आयोग ने साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर माना कि दर्जी ने समय पर सेवा न देकर स्पष्ट रूप से "सेवा में कमी" की है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिकायतकर्ता ने समय से भुगतान किया और सेवा प्राप्त करने की पूरी कोशिश की, लेकिन दर्जी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहा। इससे महिला को मानसिक तनाव और अपमान झेलना पड़ा।

अहमदाबाद उपभोक्ता आयोग ने दर्जी को आदेश दिया कि वह 4,395 रुपये की राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ महिला को लौटाए। इसके अलावा आयोग ने दर्जी को 2,500 रुपये मानसिक पीड़ा और मुकदमेबाजी खर्च के रूप में अतिरिक्त भुगतान करने का निर्देश भी दिया।

यह मामला उन सभी उपभोक्ताओं के लिए मिसाल बन गया है जो छोटी रकम या सीमित सेवा के मामलों में न्याय की उम्मीद छोड़ देते हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे सेवा कितनी भी छोटी क्यों न हो, उपभोक्ता को अधिकार है कि उसे समय पर, तय शर्तों के अनुसार और गुणवत्तापूर्ण सेवा मिले। वहीं सेवा प्रदाताओं के लिए यह फैसला एक सख्त चेतावनी है कि व्यवसाय में जिम्मेदारी से लापरवाही, चाहे कितनी भी मामूली लगे, कानून के तहत जवाबदेही तय करती है।